राष्ट्रीय छात्रशक्ति

शिक्षा क्षेत्र की प्रतिनिधि पत्रिका

वर्ष : 30 अंक : 7 जनवरी – फरवरी 2008

अभाविप 53वाँ राष्ट्रीय अधिवेशन

राष्ट्रीय अधिवेशन का प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए दैनिक जागरण समूह के अध्यक्ष श्री योगेन्द्र मोहन गुप्त

Shri B.Surendran (National Joint Org. Secretary) addressing 'Deshabhakthi Sandesha Yathra' conducted by ABVP Mangalore (Karnataka) to celebrate the 150 years of the first freedom struggle.

Governor Shri. V.S. Kokje distributing prizes to the winners of the State Level General Knowledge Competition organized by ABVP at Solan (Himachal Pradesh)

राष्ट्रीय
छात्रशक्ति
शिक्षा क्षेत्र की प्रतिनिधि पत्रिका
वर्ष : 31 अंक : 7 ● जनवरी–फरवरी 2008

संरक्षक
अतुल कोठारी
संपादक
डा. मुकेश अग्रवाल
प्रबंध संपादक
नितिन शर्मा

संपादक मंडल
संजीव कुमार सिन्हा
आशीष कुमार 'अंशु'
उमाशंकर मिश्र

डा. रंजीत ठाकुर द्वारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, बी–50, क्रिश्चियन कॉलोनी, पटेल चेस्ट, दिल्ली–110007 के लिए प्रकाशित एवं पुष्पक प्रेस, 119, डीएसआईडीसी कॉम्प्लेक्स, ओखला, फेज–1, नई दिल्ली–20 द्वारा मुद्रित

फोन : 011 – 23093238 , 27662477
E-mail : chhatrashakti@gmail.com
Website : www.abvp.org

मूल्य : एक प्रति रुपए 10/–

छात्रशक्ति

"राष्ट्रीय छात्रशक्ति" की ओर से सभी पाठकों एवं देशवासियों को *होली* की हार्दिक शुभकामनाएँ।

विषय सूची

दिल्ली के द्वार से, गंभीर विमर्श 4
53वाँ राष्ट्रीय अधिवेशन (प्रतिनिधि सभा) 11
राष्ट्रीय अधिवेशन में प्रारित प्रस्ताव 13
WOSY International Seminar - Report 17

प्रमुख लेख

विचार ही पढ़ाइए – विचारधारा नहीं 7
सवालों के घेरे में देवबंद की नियत 21
जरूरत है, मामले की गंभीरता को समझने की 24

परिचर्चा

पश्चिम में घुलती हिंदी भाषा 25
परिषद गतिविधियां 27

आह्वान

* क्या आप देश की वर्तमान दशा पर चिन्तित हैं?
* क्या आपको दृढ़ विश्वास है कि सामाजिक परिवर्तन लाने में छात्र–युवा ही सक्षम हैं?

यदि हां

* तो अपने क्षोभ को शब्द दीजिए और विश्वास कीजिए,आपमें क्षमता है कलम की नोंक से दुनिया का रुख बदलने की।
* अपने विचारों को साहित्य की किसी भी विधा में शब्द दें तथा राष्ट्रीय छात्रशक्ति द्वारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद,136,नॉर्थ एवेन्यू नई दिल्ली–110001 को प्रेषित करें।

वैधानिक सूचना : राष्ट्रीय छात्रशक्ति में प्रकाशित लेख एवं विचार रचनाओं में व्यक्त दृष्टिकोण सम्बन्धित लेखकों के हैं। सम्पादक, प्रकाशक, एवं मुद्रक का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है। समस्त प्रकार के विवादों का न्यायिक क्षेत्र दिल्ली रहेगा।

दिल्ली के द्वार से, गंभीर विमर्श

गुरुभक्त परिवार प्रकाशन द्वारा प्रकाशित पुस्तक 'दिल्ली के द्वार तक' के लेखक आचार्य श्री विजय रत्नसुंदरसूरि जी ने इस पुस्तक के माध्यम से उन विषयों को बहस के केन्द्र में लेकर आए हैं, जिनपर आमतौर पर लोग–बाग बचने का प्रयास करते हैं। यह पुस्तक साक्षात्कार आधारित है। इसमें आचार्य जी ने विभिन्न क्षेत्रों के श्रेष्ठ सज्जनों से उनके क्षेत्र की कमियों और श्रेष्ठताओं पर चर्चा की। आचार्यजी की साफगोई पुस्तक की खासियत कही जा सकती है।

इस पुस्तक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक श्री कुप्पसी सुदर्शन के साथ सेक्स एजुकेशन के संबंध में बात करते हुए आचार्यजी ने खेद व्यक्त करते हुए कहा कि मुझे इस बात की अत्यन्त पीड़ा है कि आग लगाने वालों ने तो आग लगा दी है परंतु फायर ब्रिगेड वाले सोए हुए हैं। मेरी इच्छा है कि आप इस विषय को राष्ट्रीय स्तर पर उठाएं। विषय की गंभीरता पर चर्चा करते हुए पु.सरसंघचालक ने सेक्स एजुकेशन के पीछे छुपे हुए उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि अमेरिका जैसे देश जानते हैं कि भारत की सबसे बड़ी शक्ति उसकी परिवार व्यवस्था है। योगाचार्य बाबा रामदेव ने यौनशिक्षा के संबंध में बातचीत के क्रम में एक अच्छा सवाल उठाया– जिन देशों ने अपने यहां यौन शिक्षा शुरू की थी, उनमें से किसी भी देश को इसमें सफलता मिली क्या? क्या यौन शिक्षा की वकालत करने वाले किसी ऐसे एक देश का नाम बताएंगे?

इस पुस्तक में देशभर के विभिन्न विषयों के विद्व के साथ आचार्यजी की जिन गंभीर मुद्दों पर चर्चा हुई है वह आंख खोलने वाली है और सोचने पर मजबूर करती है। इस पुस्तक में राजनीतिक, सामाजिक, विधि, पत्रकारिता आदि विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से उनकी बातचीत संकलित है। जिन लोगों से बातचीत हुई है, उनमें दिल्ली के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री साहिब सिंह वर्मा, उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री आरसी लाहोटी, शिक्षा बचाओ समिति के राष्ट्रीय संयोजक श्री दीनानाथ बत्रा, पंजाब केसरी के प्रधान संपादक स्वदेश भूषण, योगाचार्य बाबा रामदेव, रा.स्व संघ के सरसंघचालक श्री कुप्पसी सुदर्शन आदि नाम प्रमुख हैं।

केन्द्र सरकार की तुष्टीकरण नीति के खिलाफ अभाविप चलायेगी देशव्यापी आन्दोलन

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री श्री सुरेश भट्ट ने कहा कि 11 पंचवर्षीय योजना मे केन्द्र सरकार द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों की सुविधा में कटौती करना छात्रहित में नही है। उन्होने कहा कि 60 प्रतिशत से कम अंक पाने वाले छात्रों की सारी सुविधाएं समाप्त करने का प्रस्ताव ही योजना में है,जिसे केन्द्र सरकार वापस नहीं लेती तो परिषद देश भर में उग्र आन्दोलन चलायेगा । श्री भट्ट ने यह बात पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही । उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति, जनजाति छात्रों की छात्रवृति और छात्रावास जैसी सुविधाओं को समाप्त करने का यू.पी.ए सरकार का षंडयंत्र सामाजिक न्याय के लिए खतरा है। उन्होने बताया है कि परिषद के प्रतिनिधि मंडल ने देश भर में 1200 छात्रावासों का सर्वे किया । इसमें पाया गया है कि छात्रों को न तो अच्छे कमरे सुलभ है और न ही अच्छा भोजन आदि सुविधाये । इससे यह साफ जाहिर है कि केन्द्र सरकार द्वारा छात्रावासों पर खर्च किये जा रहे करोड़ो रूपये बेकार जा रहे है। श्री भट्ट ने कहा कि केन्द्र सरकार एक ओर तो अल्पसख्यक सुविधाओं को बढ़ाने की बात कर रही है तो दूसरी ओर अनुसूचित जाति, जनजाति के छात्रों की सुविधाओं में कटौती कर तुष्टीकरण नीति अपना रही है जिसे परिषद कार्यकर्ता कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे । उन्होंने केन्द्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर प्रस्ताव वापस नहीं हुआ तो परिषद देशव्यापी आन्दोलन चलायेगा । उन्होंने छात्रों का आह्वान किया कि सरकार की तुष्टीकरण नीति के खिलाफ एकजुट होकर विरोध करें ।

नौजवानों को मुख्यधारा से अलग करने का षड्यंत्र

संप्रग सरकार की हिंदू विरोधी भावनाएं लगातार बढ़ रही हैं। जो काम मुगलों और अंग्रेजों ने नहीं किया उसे सोनिया गांधी की अगुवाई वाली केन्द्र सरकार अंजाम दे रही है। एक ओर सरकार शिक्षा में अल्पसंख्यकवाद को पुरस्कृत करने में जुटी हुई है तो वहीं दूसरी ओर हिन्दुओं की आस्था से खिलवाड़ करने से बाज नहीं आ रही है। ज्ञात हो कि दिल्ली विश्वविद्यालय में स्नातक कला(बीए) इतिहास ऑनर्स (द्वितीय वर्ष) के पाठ्यक्रम में शामिल 'एनशिएंट कल्चर इन इंडिया' पुस्तक में भगवान राम तथा रामायण से संबंधित तथ्यों को तोड़–मरोड़ कर पेश किया गया है, इसके चलते करोड़ों हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई हैं। इस आपत्तिजनक अंशों को हटाने की मांग को लेकर अभाविप छात्रों के बीच जागरण अभियान चला रही है। इसी कम में गत 25 फरवरी को विद्यार्थी परिषद के बैनर तले छात्र दिल्ली विश्वविद्यालय के इतिहास विभागाध्यक्ष के समक्ष अपने विचार रखने पहुंचे तो उन्होंने छात्रों की बात सुनने से इंकार कर दिया। इससे उत्तेजित होकर छात्र विभागाध्यक्ष के खिलाफ नारे लगाने लगे। विश्वविद्यालय प्रशासन के इशारे पर पुलिस ने छात्रों के साथ बदसलूकी की और विद्यार्थी परिषद के चार कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया।

दिल्ली विश्वविद्यालय में स्नातक कला (बीए) इतिहास ऑनर्स (द्वितीय वर्ष) के पाठ्यक्रम में शामिल 'एनशिएंट कल्चर इन इंडिया' पुस्तक में विद्यार्थियों को जो पढ़ाया जा रहा है,उससे किसी भी देशभक्त का खून खौल उठेगा– ◆ रावण और मंदोदरी की कोई संतान नहीं थी। दोनों ने शिवजी की पूजा की। शिवजी ने उन्हें पुत्र प्राप्ति के लिए आम खाने को दिया। गलती से सारा आम रावण ने खा लिया और उसे गर्भ ठहर गया। दुःख से बेचैन रावण ने छींक मारी और सीता का जन्म हुआ। सीता रावण की पुत्री थी। उसने उसे जनकपुरी के खेत में त्याग दिया। ◆ हिन्दुओं की मति भ्रमित करने के लिए कहा गया कि हनुमान छुटभैया एक छोटा सा बंदर था। हनुमान की अवमानना करते हुए लिखा गया है कि वह एक कामुक व्यक्ति था वह लंका के शयनकक्षाओं में झांकता रहता था और वह स्त्रियों और पुरुषों को आमोद–प्रमोद करते बेशर्मी से देखता फिरता था। ◆ रावण का वध राम से नहीं लक्ष्मण से हुआ। ◆ रावण और लक्ष्मण ने सीता के साथ व्यभिचार किया। और स्नातक कला(प्रथम वर्ष) में पढ़ाया जा रहा है ◆ न ऋग्वेद में कहा गया है कि स्त्रियो का स्थान शूद्रों तथा कुत्तों के समान है। ◆ स्त्रियों को वेद पढ़ने पढ़ाने का कोई भी अधिकार नहीं था और न ही वह धार्मिक किया–कर्म कर सकती थी। ◆ अथर्ववेद में महिलाओं को केवल संतान उत्पन्न का साधन माना जाता था। ◆ वेदों के अर्थों का अनर्थ कर महिलाओं को घृणा की दृष्टि से दिखलाया गया है।

केंद्र सरकार के साढ़े तीन वर्ष के कार्यकाल के दौरान लिए गये निर्णयों पर नजर डालने यह स्पष्ट हो जाता है कि हिंदुओं को अपमानित करना ही इस सरकार का प्रमुख कार्य है। सरकार ने पहले रामसेतु के मुद्दे पर गलत हलफनामा पेश कर कहा था कि भगवान राम का अस्तित्व ही नहीं है। डेनमार्क में पैगम्बर मोहम्मद के कार्टून पर भारत सरकार ने अधिक रूप से चिंता और खेद जताया लेकिन जिस एम.एफ. हुसैन ने मां सीता और भारतमाता के अश्लील चित्र बनाए, उस पर कोई बयान तक नहीं दिया। राम के अस्तित्व पर सवाल खड़ा करने वाले रामद्रोही ही नहीं वरना राष्ट्रद्रोही है। दरअसल, यह मार्क्स–मैकाले के मानस मस्तिष्कों का कमाल है। जो राष्ट्रविरोधी कचड़ा उनके दिमाग में होता है वही विभिन्न माध्यमों से वे बाहर अभिव्यक्त करते रहते हैं। कभी पेंटिंग बनाकर, लेख लिखकर, पाठ्यक्रमों में गलत तथ्य समाहित कर। वे जानते है कि विदेशी विचारधारा भारत में तभी प्रबल हो सकता है जब नौजवानों में राष्ट्रनायकों के प्रति हीन भावना उत्पन्न हो जाए। विद्यार्थी परिषद की स्पष्ट मान्यता है कि किसी को भी किसी भी धर्म का अपमान करने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिये। देश के छात्र–नौजवान किसी भी हालत में राष्ट्रनायकों का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे और विद्यार्थी परिषद का आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक दिल्ली विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम से 'एनशिएंट कल्चर इन इंडिया' पुस्तक को हटाया नहीं जाता है।

दिल्ली में ऐतिहासिक रामसेतु रक्षा महासम्मेलन में रामभक्तों ने दी चेतावनी

अब याचना नहीं.....

रूक्मिणी देवी । उम्र करीब 65 । एक हाथ से सर पर भारी पोटली संभाले और दूसरे हाथ से 7–8 वर्ष के अपने पोते की अंगूली थामे । छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले से आई रूक्मिणी देवी बमुश्किल अपने सहयोगियों के साथ चल पा रही थी । मगर चेहरे पर किसी थकान के भाव नही थे, बल्कि आंखों में चमक, एक ललक थी, रामसेतु रक्षा महासम्मेलन स्थल पर पहुँचने की। 30 दिसम्बर की सुबह रोहिणी के स्वर्ण जयंती पार्क की ओर जाने वाली सभी सडकों पर यही दृश्य था । ढोलक, मंजीरों की ताल पर राम भजन गाते देश के एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक के आबाल वृद्ध टोलियों में सम्मेलन स्थल की ओर बढ रहे थे । ये वे रामभक्त थे जो सेकुलर सरकार के रामसेतु तोडने के फैसले के विरूद्ध अपना संगठित रोष प्रकट करते दिल्ली पहुँचे थे लाखों की संख्या में ।

मंच पर एकत्र थी भारत की पूज्य संतशक्ति । मंच से सबने हाथ उठाकर 'जय श्रीराम' गुंजाया तो उसकी गूंज साऊथ ब्लाक तक जरूर पहुंची होगी और उसने इस देश में हिन्दुओं के मान बिन्दुओं का उपहास उडाने वाली सरकार को सचेत कर दिया होगा कि अब हिन्दू सब कुछ चुपचाप सहते नही रहेंगे, वे संगठित होकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे । संतों ने श्रद्धालुओं के साथ रामसेतु रक्षा का संकल्प लिया ।

सम्मेलन को सबसे पहले संबोधित किया विश्व हिन्दू परिषद के अन्तर्राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अशोक सिंघल ने । उन्होंने रामसेतु के धार्मिक, ऐतिहासिक और सामरिक महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि जो राम और रामसेतु के अस्तित्व से इन्कार करता है उसे इस देश में रहने का हक नही है । श्रीराम जन्मभूमि न्यास (अयोध्या) के अध्यक्ष महंत नृत्यगोपालदास जी ने कहा कि धर्म विरोधी सेकुलर हमारी परंपराओं को नष्ट कर रहे हैं ।

तुलसी पीठाधीश्वर पूज्य राम भद्राचार्य जी ने कहा कि सम्मेलन में भक्तों की असाधारण उपस्थिति उन्हें आभास दे रही है कि रामविरोधियों का पतन अब दूर नही है ।

साध्वी ऋतम्भरा ने रामभक्तों को रामसेतु रक्षा का संकल्प दिलाया और याद दिलाया हिन्दुओं का सहज शौर्य। उन्होंने कहा कि सहिष्णुता त्याग कर अब आसुरी प्रवृत्तियों के दमन का समय आ गया है । संस्कृति विरोधियों को परास्त करना ही होगा ।

रा. स्व. संघ के सरसंघचालक श्री कु.सी. सुदर्शन ने सरकार के उन सभी तर्कों को एक–एक कर ध्वस्त किया जो इसे तोड़ने के पक्ष में सरकार की ओर से प्रस्तुत किये गए हैं । उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार के प्रधानमंत्री कम्युनिस्टों और द्रमुक की धमकियों को अनदेखा करने की हिम्मत दिखाएं और रामसेतु तोड़ने से बाज आएं ।

सम्मेलन हेतु तमिलनाडु से विशेष रूप से आए स्वामी राघवानंद जी ने तमिल भाषा में रामसेतु रक्षा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसका हिन्दी में भाषान्तर किया विहिप के कार्याध्यक्ष श्री वेदान्तम ने । जनता पार्टी के अध्यक्ष डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी ने तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता द्वारा प्रेषित संदेश पढ़ा। विहिप के महामंत्री डा. प्रवीण भाई तोगड़िया ने साफ शब्दों में कहा कि अब समय आ गया है जब हिन्दू समाज अपनी एकजुट शक्ति का प्रदर्शन करे और राम विरोधी शपथ पत्र दायर करने वाली सरकार की चूलें हिला दे ।

पेजावर स्वामी पूज्य विश्वेशतीर्थ ने भी कहा कि अब विनय नही, कोप दिखाना होगा । आचार्य धर्मेन्द्र ने सबसे आखिर में श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि विदेशनिष्ठ और रोम भक्त ताकतें हमारे धर्म, संस्कृति और आस्था पर प्रहार कर रही हैं, परन्तु अब हम यह सहन नहीं करेंगे । अंत में सम्मेलन के अध्यक्ष पूज्य शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती ने आशीर्वचन स्वरूप कहा कि हिन्दुत्व पर आघात के विरूद्ध समाज एकजुट हो। एकजुट हिन्दू शक्ति के आगे हिन्दुत्व विरोधी परास्त होंगे ।

सुबह 11 बजे शुरू होकर यह महासम्मेलन शाम 5 बजे समाप्त हुआ । इस दौरान विशाल स्वर्ण जयंती पार्क लघु भारत का रूप ले चुका था, जहां ऊंच–नीच, जाति–पाति, बोली, भाषा की सीमाएं नही थीं, सब एक थे, सब राम भक्त। महासम्मेलन में विभिन्न विशिष्टजन द्वारा प्रेषित संदेश भी पढ़े गए ।

विचार ही पढ़ाइए - विचारधारा नहीं

– अवनिजेश अवस्थी –

हिंदुस्तान की बाकी भाषाओं के संदर्भ में तो पता नही, हिंदी में एक मुहावरा बहुधा प्रयोग में आता है – 'अपनी–अपनी रामकहानी' । मुहावरों के निहितार्थ बड़े गहरे होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं लेकिन इस मुहावरे के प्रचलित होने का एक कारण यह भी लगता है कि भारतवर्ष की शायद ही कोई भाषा या बोली हो जिसमें रामकथा न कही गई हो – जिसकी अपनी रामकहानी (रामकथा) न हो । यही नहीं, राम की लीला स्थली कहे जाने वाले भूभाग यानी वर्तमान उत्तर, मध्य और बिहार प्रदेश के लोकगीतों तक में रामकथा ही भरी पड़ी है । सच्चाई तो यह है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक कोई ऐसा प्रसंग, अवसर, त्यौहार और संस्कार नहीं जिसमें रामकथा न कही जाती हो । इस रामकथा के संदर्भ में उल्लेखनीय बात यह है कि भारत के साथ ही समूचे दक्षिण पूर्व एशिया का भी कोई ऐसा देश नही जिसकी अपनी रामकथा न हो – भारत की तो आर्य–द्रविड़ कही जाने वाली सभी भाषाओं में रामकथा का सृजन हुआ ही है ।

सिर्फ स्मरण दिलाने के लिए यह उल्लेख भी है कि फादर कामिल बुल्के नामक हिंदी के विद्वान ने भी रामकथा : उत्पत्ति और विकास नामक शोध ग्रंथ तैयार किया था जो आज तक रामकथा के क्षेत्र में शोध का मानक है । और यह रामकथा है जिसके बारे में रामधारी सिंह दिनकर ने 'संस्कृति के चार अध्याय' नामक अपने ग्रंथ में, जिसकी प्रस्तावना पं. जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी, लिखा था– किंतु फिर भी इससे यह बात सरलता से सिद्ध हो जाती है कि रामकथा ने इस देश की संस्कृति की कितनी गंभीर सेवा की है, और कैसे इस कथा को लेकर सारा देश लगभग एक आदर्श की ओर उन्मुख रहा है। इसके साथ अगर तिब्बत, सिंहल,खोतान,हिंद–चीन, श्याम, ब्रह्मदेश, कश्मीर और हिन्देशिया में प्रचलित रामकाव्यों की सारिणी मिलादें तो सचमुच में ही यह माना पड़ेगा कि रामकथा न केवल भारतीय वरन् एशियाई संस्कृति का भी एक महत्वपूर्ण तत्व बन गई थी।

एक तरफ दिल्ली विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम से सूर–तुलसी जैसे कवियों को मध्यकालीन कहकर निकाला जा रहा है तो दूसरी तरफ रामानुज जैसे किसी व्यक्ति के निहित मंतव्यों वाले लेख को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाता है । यदि रामकथा और रामायणों की सुदीर्घ परंपरा से ही विद्यार्थियों का परिचय कराना ही उद्देश्य है तो फादर कामिल बुल्के को पढ़ाया जाना चाहिए ।

'जिस रामकथा के संदर्भ में दिनकर ने ये विचार व्यक्त किए थे, उसी रामकथा से संबंधित एक लेख दिल्ली विश्वविद्यालय ने बी.ए. के विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम में निर्धारित किया है । इस लेख के विषय में तो बाद में बात करेंगे लेकिन उस पुस्तक की चर्चा पहले कर लें जिस पुस्तक से यह लेख लिया गया है । पुस्तक है सन् 1992 में प्रकाशित – "मैनी रामायणाज" और इस पुस्तककी संपादिका हैं पाउला रिचमैन। लेकिन इस पुस्तक का संपादन पाउला ने तमाम रामायणों के विषय में जानकारी देने के उद्देश्य से नहीं किया है – जैसे कि सामान्यतः प्रतीत होता है, बल्कि इस पुस्तक के संपादन के मूल में उनकी चिंता है – दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले 'रामायण' धारावाहिक के भारतीय जनमानस पर पड़ने वाले असाधारण प्रभाव की जिसे उन्होंने पुस्तक के अपने पहले लेख में ही स्वीकार किया। वे उद्धृत करती हैं 'फिलिप ल्युजेनड्रॉफ' को – 'भारतीय टेलीविजन पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों में सर्वाधिक

लोकप्रिय धारावाहिक रामायाण हो गया है. और इससे भी अधिक बात यह है कि यह एक ऐसी घटना है जिससे पहले कभी भी दक्षिणी एशिया की समस्त जनता इस प्रकार एक क्रियाकलाप में इकट्ठी हुई हो । इससे पूर्व कभी भी एक साथ इतने दर्शकों तक कोई संदेश एक साथ नहीं पहुंच पाया । रामायण धारावाहिक के इस प्रभाव से परेशान हो वे साफ लिखती हैं कि 'रामायण' की इस लोकप्रियता से से रोमिला थापर जैसे बहुत लोग विचलित थे क्योंकि उनकी दृष्टि में दूरदर्शन देश की बहुतायत जनता का नही बल्कि सिर्फ मध्य वर्ग की रूचियों को पोषित कर रहा था और बड़ी तफसील से उन्होने 'रामायण' प्रसारित होने को खतरनाक घोषित करते हुए इस पुस्तक की आवश्यकता को अनुभव किया । अब यह बात बड़ी सरलता से समझा जा सकती है कि 'रामायण' धारावाहिक के प्रसारण के 'खतरे' को भांप कर जो पुस्तक तैयार की गई होगी उसमें संकलित रामानुजम का 'थ्री हंड्रेड रामायाणाज' लेख के मूल में क्या दृष्टि रही होगी ।

मजे की बात यह है कि तीन सौ रामायण की चर्चा करने के नाम पर रामानुजम ने अपनी मर्जी से केवल पांच रामायणों को चुन कर और बिना संदर्भों के रामकथा के संबंध में तमाम अनर्गल किस्सों की चर्चा की है ।

स्नातक स्तर के विद्यार्थियों को प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति के नाम पर बाल्मीकि से लेकर संस्कृत की सैकड़ों रामायण और गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस की बजाय आप नितान्त उन अल्पज्ञात कृतियों को जो अपने भाषा समाज में भी ज्यादा नहीं जानी जाती, पढ़ा कर क्या हासिल करना चाहते हैं? साफ है कि मंतव्य ज्ञान, जानकारी या शिक्षा का नहीं विशुद्ध राजनीतिक है । पाठ्यक्रम निर्धारित करने वालों में से कोई भी क्या यह जवाब दे सकता है कि सीता रावण के छींक मारने से पैदा हुई थी – यह पढ़ा कर आप विद्यार्थियों के कौन से ज्ञान की अभिवृद्धि करना चाहते हैं । हां, अगर किसी को तमाम रामायणों का तुलनात्मक अध्ययन करना हो तो शोध करने के लिए कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र है, वैसे इस तरह के पर्याप्त शोध हो भी चुके हैं । पाठ्यक्रम के विषय के निर्धारण का मूल आधार होता है विषय की प्रामाणिकता और उसका निर्विवाद होना । एक तरफ आवाज यह उठतनी रही है कि विदेशी आकाओं के बर्बर अत्याचारों – जो कि हमारे निकटतम इतिहास का पूर्णतः ज्ञात सत्य है – को इसलिए नहीं पढ़ाया जाना चाहिए कि इससे दो समुदायों के बीच वैमन्सय बढ़ता है, और दूसरी तरफ नितान्त अप्रमाणिक और किसी की कपोल–कल्पना पाठ्यक्रम में लगाकर आप उसे पढ़ने को विद्यार्थियों को बाध्य करते हैं ।

सवाल है कि क्या नेहरू और लेडी माउंटबेटन के संबंधों को लेकर लिखी गयी कृति को भी आप पाठ्यक्रम में लगाने का साहस दिखा सकते हैं? एक तरफ दिल्ली विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम से सूर–तुलसी जैसे कवियों को मध्यकालीन कहकर निकाला जा रहा है तो दूसरी तरफ रामानुज जैसे किसी व्यक्ति के निहित मंतव्यों वाले लेख को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाता है । यदि रामकथा और रामायणों की सुदीर्घ परंपरा से ही विद्यार्थियों का परिचय कराना ही उद्देश्य है तो फादर कामिल बुल्के को पढ़ाया जाना चाहिए । लेकिन मंतव्य तो साफ है कि विद्यार्थियों को विचार नही विचारधारा पढ़ानी है, लेकिन इस प्रकार क्या सचमुच कोई विचारधारा पुष्ट हो सकती है, यदि यह सही होता तो क्या सोवियत संघ का कभी विघटन होता ?

गांधी जी के शैक्षिक विचार

अलबता एक चीस ऐसी जरूर है कि जिसके लिये विद्यार्थी या छात्रों का हड़ताल करना उनका कर्तव्य है। लाहौर के यूथ वेलफेयर ऐसोसिएशन के अवैतनिक मंत्री का एक पत्र मुझे मिला है इस पत्र में अश्लीलता और कामुकता से भरे काफी नमूने पाठ्यपुस्तकों से उद्धत किये गये है जिन्हें विभिन्न विश्वविद्यालयों ने अपने पाठ्यकमों में रखा है.....

यह एक ऐसा प्रसंग है जो विद्यार्थीयों या छात्रों द्वारा की गई हड़ताल को न सिर्फ उचित ठहराता है बल्कि मेरी राम में उनका यह कर्त्तव्य हो जाता है कि ऐसा साहित्य के खिलाफ वे विद्रोह भी करे।

विवादित पुस्तक को हटाने की मांग

शिक्षा बचाओ आंदोलन समिति और अभाविप का आन्दोलन

दिल्ली विश्वविद्यालय में स्नातक कला इतिहास ऑनर्स (बीए) द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में शामिल 'एनशिएंट कल्चर इन इंडिया' पुस्तक के कुछ अंशों को हटाने की मांग को लेकर शिक्षा बचाओ आंदोलन समिति और अभाविप छात्रों के बीच जागरण अभियान चला रही है। दिल्ली विश्वविद्यालय के इतिहास के सिलेबस व संकलित पुस्तक में श्रीराम, सीता और हनुमान का अपमान कर जाफरी और उपिन्दर सिंह ने करोड़ों हिन्दुओं की भावनाओं को ठेस पहुँचाया है।

1992 में एक महिला जिनका नाम 'पोला रिचमैन' है (साहित्य में स्नातक) एक पुस्तक संपादित की जिसका शीर्षक है 'Many Ramayanas'. लेखिका अपनी पुस्तक की प्रस्तावना देते हुए लिखती हैं कि अधिकतर भारतीयों और साउथ ईस्ट एशिया में बसे लोगों की आस्था के केन्द्र राम हैं और इस आस्था को और दृढ़ किया 80 के दशक में आये 'रामानन्द सागर' के Serial 'रामायण' ने। वो यह भी लिखती हैं "While most scholars continue to rely on Valmiki's Sanskrit 'Ramayana', as the authoritative version of the tale, the contributors of this volume don't." अर्थात् प्रस्तावना में ही उन्हें विदित है कि राम करोड़ों हिन्दुओं की आस्था के के केन्द्र हैं और आज भी हर विषय के विद्वान वाल्मिकी रामायण को ही प्रमाणिक मानते हैं, परन्तु इस पुस्तक में संकलित मुट्ठी भर लोगों के लेख ऐसा नहीं मानते।

इसी पुस्तक में संकलित ए. के रामानुज का अध्याय '300 रामायण' जो राम–सीता और हनुमान के प्रति बहुत ही अपमानजनक है, छात्रा–छात्राओं को जबरदस्ती पढ़ाया जा रहा है (Compulsory Text - See Syllabus of History).

जब यह पुस्तक भारत में पुनः प्रकाशित हुई तब इसका शीर्षक था 'Questioning Ramayana' अर्थात् प्रमाणिक रामायण पर नकारात्मक प्रतिक्रिया देने वाली पुस्तक का अपमानजनक अध्याय पढ़ाने वाला दिल्ली विश्वविद्यालय करोड़ों हिन्दुओं की धार्मिक भावनाएँ भड़काने का ही काम नहीं कर रहा, इस प्रकार के syllabus के नाम पर इतिहास में तथ्य नहीं किंवदन्तियाँ या कुछ ही मुट्ठी भर लोगों के विचार पढ़ाने की तानाशाही भी कर रहा है।

अपमानजनक, दुर्भावनापूर्ण, विद्वेष उत्पन्न करने वाले पाठ्यक्रम में से कुछ उदाहरण – भारत में ही नहीं पूरे विश्व में हनुमान पर आस्था रखने वाले करोड़ों हिन्दुओं की भावना को ठेस पहुँचाते हुए लिखा है कि हनुमान छुट भैया एक छोटा–सा बन्दर था। हनुमान की अवमानना करते हुए लिखा है कि वह एक कामुक व्यक्ति था, वह लंका वेफ शयनकक्षों में झांकता रहता और स्त्रियों, पुरुषों को आमोद–प्रमोद करते बेशर्मी से देखता फिरता देखा करता था। विकृत मानसिकता वाले रामानुज इन्द्र के शरीर पर लाखों स्त्रीजन के उग जाने की असभ्य व्याख्या करते हैं।

रावण और मंदोदरी की कोई सन्तान नहीं थी। दोनों ने शिवजी की पूजा की। शिवजी ने उन्हें पुत्रा प्राप्ति के लिए आम खाने को दिया। गलती से सारा आम रावण ने खा लिया और उसे गर्भ ठहर गया। बड़ी स्वच्छन्दता से रावण के नौ मास के गर्भधरण का अभद्र वर्णन किया है।

सीता रावण की छींक से पैदा हुई और इस कहानी का आधार उन्होंने कन्नड़ भाषा में सीता शब्द के अर्थ को बनाया है (कन्नड़ में सीता का अर्थ है छींक)। रावण और लक्ष्मण ने सीता के साथ व्यभिचार किया। रावण का वध राम से नहीं लक्ष्मण से हुआ।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा इस विषय के विरोध में चलाए गये आन्दोलन की एक

झलक :

23 जनवरी 2008 – विद्यार्थी परिषद ने Vice Chancellor को एक ज्ञापन दिया। जिसमें उपर दिये सभी उदाहरण बताते हुए इस पाठ को वापस लेने की अपील की गई। इस प्रकार के अपमानजनक पाठ से एक जन–आन्दोलन के भड़कने की संभावना भी जताई गई।

29 जनवरी 2008 – विद्यार्थी परिषद और दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यापकों ने एक शान्तिपूर्ण प्रदर्शन इतिहास विभाग और VC Office के सामने किया। इस प्रदर्शन में भी इतिहास विभाग के अध्यक्ष और VC को ज्ञापन दिया गया। इतिहास के विभागाध्यक्ष और Proctor के द्वारा जल्द से जल्द इस विषय पर कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया। आश्वासन देने के बावजूद लगभग एक महीने तक विश्वविद्यालय प्रशासन सोता रहा। 25 फरवरी को परिषद के छात्रा–छात्रा पुलिस और मीडिया की उपस्थिति में फिर से इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष से मिले जिन्होंने बातचीत के दौरान अड़ियल एवं आक्रामक रवैया अपनाया और 5 छात्रों के प्रतिनिधि के साथ अशिष्ट व्यवहार किया। ये छात्र जिनका भगवान राम के प्रति अगाध विश्वास है उनकी भावनाओं को अपमानित करने व भड़काने के लिए इतिहास विभाग के अध्यक्ष व दिल्ली प्रशासन दोषी हैं।

पुलिस ने गरमागरम बहस के दौरान परिषद छात्रों को जबरन उठा कर विभाग से बाहर निकाला और उस समय कोई कार्यवाही न कर रात को दो छात्रों को और सुबह एक छात्र को गिरफतार किया। यदि परिषद दोषी थे तो उन्हें पुलिस की मौजुदगी के बावजूद घटनास्थल पर ही गिरफतार क्यों नहीं किया गया। यह स्पष्ट दर्शाता है कि गिरफतारियाँ बाद में विश्वविद्यालय के दबाव की वजह से हुई, क्योंकि हिन्दुओं के प्रति अपमानजनक मगज की संकलनकर्ता डॉ. उपिन्दर सिंह, माननीय प्रधानमंत्री जी की बेटी हैं। विद्यार्थी परिषद विश्वविद्यालय प्रशासन से अपील करते हैं कि बिना देरी के इस अपमानजनक, विद्वेषपूर्ण और जनमानस की भावनाओं को आघात पहुँचाने वाले अध्याय को इतिहास के पाठ्यक्रम से हटाया जाये। इस विषय पर कोर्ट ने भी लिखा है कि किसी भी धार्मिक भावनाओं को अपमानित करने का अधिकार नहीं है। यदि कोई ऐसा करता है कि उसे दंडित करने का प्रावधान है।

विश्वविद्यालय प्रशासन को परिषद चेतावनी देता है कि यदि प्रशासन ने यही रवैया अपनाया तो पूरे भारत में एक जबरदस्त आन्दोलन आरंभ हो जायेगा और दिल्ली विश्वविद्यालय इससे अछूता नहीं रहेगा। इस पर होने वाली प्रत्येक प्रतिक्रिया के जिम्मेदार इतिहास विभागाध्यक्ष, VC और उपिन्दर कौर ही होंगी।

'एनशिएंट कल्चर इन इंडिया' पुस्तक के कुछ अंशों को हटाने की मांग को लेकर शिक्षा बचाओ आंदोलन समिति ने 28 फरवरी को जंतर–मंतर पर विशाल धरना–प्रदर्शन का आयोजन किया। प्रदर्शन के बाद कार्यकर्ताओं ने संसद की ओर मार्च किया। धरना में पूर्व केंद्रीय मंत्री डा. मुरली मनोहर जोशी, प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा, शिक्षा बचाओ आंदोलन समिति के राष्ट्रीय संयोजक श्री दीनानाथ बत्रा, राष्ट्रीय संयोजक श्री अतुल कोठारी, विश्व हिंदू परिषद के महासचिव श्री राष्ट्रप्रकाश सहित अनेक विशिष्टजनों ने हिस्सा लिया।

गौरतलब है कि पिछले दिनों दिल्ली विश्वविद्यालय में स्नातक कला इतिहास ऑनर्स (बीए) द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में शामिल 'एनशिएंट कल्चर इन इंडिया' पुस्तक के कुछ अंशों को हटाने की मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय परिसर में विरोध–प्रदर्शन किया था।

इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री डा. मुरली मनोहर जोशी ने कहा कि विश्वविद्यालय की किताब में हिंदू देवी–देवताओं पर की गई टिप्पणियां भारतीय संस्कृति के साथ खिलवाड़ है, जिसे भारतीय जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। पुस्तक में भारतीय वेदों, राम, लक्ष्मण और हनुमान के बारे में अपशब्दों का प्रयोग किया गया है, ऐसी पुस्तक हमारे नौजवानों को मुख्य धारा से अलग करती है और उन्हें अपने राष्ट्र, धर्म और महाकाव्यों से नफरत करना सिखाती है। उन्होंने कहा कि इस किताब के संपादक डा. उपेन्द्र सिंह को तत्काल जनता से माफी मांगनी चाहिए।

सांसद प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा ने कहा कि एसके रामानुजन एक भाषाविद है न कि कोई इतिहासकार। इसलिए उनके लिखित अंशों को जल्द से जल्द हटाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वे इस मुद्दे को अपने स्तर पर संसद में उठाएंगे। शिक्षा बचाओ आंदोलन समिति के राष्ट्रीय संयोजक श्री दीनानाथ बत्रा ने केंद्र सरकार से इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप किए जाने की मांग की। ■

53वॉ राष्ट्रीय अधिवेशन (प्रतिनिधि सभा)

1–4 दिसबर, 2007, तात्या टोपे नगर, कानपुर (मध्य उत्तर प्रदेश)

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदका 53वॉं राष्ट्रीय अधिवेशन (प्रतिनिधि सभा) मध्य उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में दि. 1–2 दिसम्बर 2007 को सम्पन्न हुआ । 53वॉं राष्ट्रीय अधिवेशन 1857 में स्वराज्य और स्वधर्म के लिए निर्णायक लड़ाई छेड़ने का संकल्प लेकर तन–मन–धन समर्पित करने वाले नाना साहब पेशवा, तात्या टोपे एवं रानी लक्ष्मीबाई का केन्द्र रहे कानपुर (मध्य उत्तर भारत) में विशेष रूप से बसाए गए 'तात्या टोपे नगर' में दि. 1 से 4 दिसम्बर, 2007 को सम्पन्न हुआ । अधिवेशन पण्डाल 'भगतसिंह सभागार' के नाम से बसाया गया था । 53वें राष्ट्रीय अधिवेशन में पूर्व निर्धारित अपेक्षित सूची में से 366 जिलों से 479 स्थानों से कुल 958 प्रतिनिधि राष्ट्रीय अधिवेशन (प्रतिनिधि सभा) में सहभागी हुए । जिनमें 490 छात्र, 205 छात्राएँ, 90 शिक्षक तथा 268 पूर्णकालिक कार्यकर्ता समाहित हैं ।

तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. रामनरेश सिंह एवं महामंत्री श्री सुरेश भट्ट ने दि. 1 दिसम्बर, 2007 को सांयकाल सभी प्रतिनिधियों की उपस्थिति में ध्वजारोहण करते हुए अधिवेशन का सूत्रपात किया । विद्यार्थी परिषद् के वर्ष 2006–07 की गतिविधियाँ अर्थात् हैदराबाद राष्ट्रीय अधिवेशन में कानपुर राष्ट्रीय अधिवेशन तक का महामंत्री प्रतिवेदन सभागार के दृकश्राव्य च्चूमत च्वपदज च्तमेमदजंजपवदद्ध के माध्यम से प्रतिनिधियों के सम्मुख रखा गया । राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा 2006–07 की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद के कार्यकाल समाप्ति के घोषणा के पश्चात निर्वाचन अधिकारी डॉ0. कैलाश शर्मा (जयपुर) ने चुनाव प्रक्रिया ने चुनाव प्रक्रिया की जानकारी देते हुए वर्ष 2007–08 के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष हेतू डॉ. रामनरेश सिंह (सहरसा, बिहार) तथा राष्ट्रीय महामंत्री हेतु श्री सुरेश भट्ट (वाराणसी, पूर्वी उ.प्र.) को पुनः एक बार सर्वानुमति से निर्वाचित घोषित किया । दोनों पदाधिकारियों ने अपना पद ग्रहण करते हुए मनोगत व्यक्त किया ।

53वें राष्ट्रीय अधिवेशन का उद्घाटन विश्व हिन्दू परिषद् के अन्तर्राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अशोक सिंघल ने दिनांक 2 दिसम्बर को दीप प्रज्वलन कर किया। उद्घाटन अवसर पर उपस्थित प्रतिनिधि, विद्यार्थी परिषद के हितैषी व शहर के गणमान्य व्यक्तियों को संबोधित करते हुए उन्होंने विद्यार्थी काल को साधन काल बताते हुए कहा कि केवल राजनीति क्षेत्र विद्यार्थियों का लक्ष्य नही होना चाहिए, क्योंकि राजनीति में सामाजिक परिवर्तन नही हो सकता । राजनीति समाज व देश के परिवर्तन में सहायक मात्र है । सामाजिक कार्य ही बदलाव ला सकते हैं ।

उद्घाटन समारोह में कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि तात्या टोपे के पौत्र विनायक राव टोपे को सम्मानित किया गया । उद्घाटन समारोह के अवसर पर मंच पर राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री, स्वागत समिति अध्यक्ष, महामंत्री एवं संयोजक तथा मध्य उत्तर प्रदेश के प्रांत अध्यक्ष व मंत्री उपस्थित थे ।

राष्ट्रीय अधिवेशन में हुए एक विशेष कार्यक्रम में वर्ष 2007 का प्रा. यशवंतराव केलकर युवा पुरस्कार आन्ध्र प्रदेश के श्री जी. सतीश रेड्डी को रक्षा से संबंधित पथ दर्शक प्रणाली (नेविगेशन सिस्टम) का विकास कर भारत को आत्मनिर्भर बनाने के महत्वपूर्ण कार्य के लिए प्रदान किया गया । समारोह के मुख्य अतिथि विज्ञान भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. के.आई. वासु ने श्री रेड्डी को 25 हजार रूपये, स्मृति चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र देकर युवा पुरस्कार से सम्मानित किया । प्रा. यशवंतराव केलकर के प्रेरणादायी प्रसंगों के द्वारा उनकी जीवनी का कथन प्रा. सुरेश गुप्ता (विदिशा, मध्य भारत) ने किया ।

राष्ट्रीय अधिवेशन में विभिन्न विषयों पर भाषण हुए। '1857 का स्वतंत्र समर वर्तमान संदर्भ में विषय पर भाषण में मा. सुरेश सोनी (सह सर कार्यवाह, रा. स्व. संघ) ने कहा कि तात्कालिक रूप से 1857 का संघर्ष प्रेरणादायी रहा, यह संघर्ष की सबसे बड़ी उपलब्धि रही । 1857 संघर्ष स्वधर्म और

स्वराज्य के लिए था ।

यह संघर्ष आज भी चल रहा है, परिस्थितयाँ बदली होंगी, लेकिन तत्व दर्शन के आधार अब इसमें आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से स्वतंत्रता लाने की आवश्यकता है । इस देश की व्यवस्थाओं को ठीक से खड़े करने की आवश्यकता है । गौरक्षा, रामजन्मभूमि, तुष्टिकरण ये आज के प्रश्न हैं । ग्राम पंचायत, न्याय व्यवस्था इनमें पारदर्शिता लाने की आवश्यकता है, 1857 की क्रांति संदेश देती है कि भावनात्मक राष्ट्रवाद का भाव जाग्रण कर इस में से एक प्रबल शक्ति का उदय हो और तुष्टीकरण से मुक्ति हो ।

'छात्र आन्दोलन की दिशा एवं हमारी भूमिका' विषय पर भाषण में डॉ. रामनरेश सिंह (राष्ट्रीय अध्यक्ष, अभाविप) ने कहा कि समाज में सबसे निर्मल वर्ग छात्र समुदाय का है, इसलिए किसी भी घटना की प्रतिक्रिया शीघ्र ही छात्रों द्वारा होती है, विश्व में जितने भी परिवर्तन हुए उन सब में छात्रों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है ।

समाज में व्यवस्था परिवर्तन, लोकतंत्र की स्थापना एवम् राजनैतिक परिवर्तनों में छात्रों की अहम् भमिका रही है । भारत, चीन, क्यूबा, मलेशिया, फ्रांस, जकार्ता, रूस आदि कई देशों में छात्र आंदोलनों के कारण बड़े परिवर्तन हुए हैं । भारत में विद्यार्थी परिषद ने अन्य छात्र संगठनों को एक दर्शन देने का कार्य करते हुए कहा कि, आज का छात्र आज का नागरिक एवम् छात्र शक्ति–राष्ट्र शक्ति । विश्व में अभाविप ने छात्र भूमिका के अन्तर्गत राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक न्याय, शिक्षा के क्षेत्र तथा आर्थिक क्षेत्र में आंदोलन के माध्यम से परिवर्तन निश्चित किया है ।

'हमारी विचारधारा एवं राष्ट्र के समक्ष चुनौतियां' विषय पर श्री दिनेश कुमार (क्षेत्रिय संगठन मंत्री, प.उ. मध्य क्षेत्र) ने कहा कि भारत का मूल चिंतन हिन्दू चिंतन है और यह सत्य सनातन और वैदिक काल से चला आ रहाहै । लेकिन आज पश्चिम का विचार और हमारे विचार से संघर्ष चल रहा है ।

आज देश में आधुनिकता के नाम पर सांस्कृतिक आक्रमण हो रहा है । हमारी संस्कृति पर जिस तरह का आक्रमण हो रहा है । उसे हम समझते हुए, वैचारिक संघर्ष की आवश्यकता है । विचारों की लड़ाई में इस देश को बचाने की आवश्यकता है । हम विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता है, हम नीव के पत्थर की तरह काम करते हैं । हम कार्य करते हैं अपने विचारों के लिए । आज हमारे राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के विचार को गली–गांवों में ले जाते हुए युगानुरूप करने की आवश्यकता है ।

अधिवेशन में चार भिन्न–भिन्न विषयों पर समानान्तर सत्र भी चलाए गये ।

राष्ट्रीय अधिवेशन में चार प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किये गये

1) केन्द्र सरकार की दिग्भ्रमित उच्च शिक्षा नीति ।
2) देश का वर्तमान परिदृश्य।
3) अनुसूचित जाति, जनजाति छात्रावास समस्या
4) श्रीराम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए ।

अधिवेशन परिसर पर एक स्मारक बनाया गया था, जिसमें झाँसी, पानीपत, हल्दीघाटी, बैरकपुर एवं 1857 की क्रांति के स्थानों की माटी देशभर से भिन्न–भिन्न स्थानों से लाकर कलश में रखी गयी थी। जो अधिवेशन में आए सभी प्रतिनिधियों के लिए प्रेरणादायी रहा ।

अधिवेशन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा किए गए अनुसूचित जाति व जनजाति छात्रावासों की सर्वे रिपोर्ट विमोचन हुआ ।

दिनांक 1 दिसम्बर को अधिवेशन स्थल पर प्रदर्शनी का उद्घाटन दैनिक जागरण समूह के अध्यक्ष श्री योगेन्द्र मोहन गुप्त ने किया । 1857 के प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के विषय पर बनाई गई प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए श्री गुप्त ने कहा कि स्व–अनुशासन के बिना कोई क्रांति नही हो सकती, जहाँ कहीं भी अनुशासनहीनता दिखाई देती है, तो विद्यार्थियों को पहल करनी चाहिए । कार्यक्रम में अभाविप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. पायल सिरोही का भाषण भी हुआ ।

वर्ष 2007 में समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के जिन गणमान्य व्यक्तियों का निधन हुआ, उनके प्रति शोक प्रस्ताव पारित किया गया ।

राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा वर्ष 2007–08 हेतू राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की घोषणा की गई । अधिवेशन के व्यवस्था

प्रमुख श्री अरूण पाठक ने व्यवस्था एवं उस में लगे सभी प्रबंधक कार्यकर्ताओं का संक्षिप्त परिचय कराया, जिनका अधिवेशन में आये सभी प्रतिनिधियों ने करतल ध्वनि से अभिनंदन किया ।

अभाविप के राष्ट्रीय संगठनमंत्री श्री सुनील आंबेकर ने 53वें राष्ट्रीय अधिवेशन का समारोप भाषण किया । उन्होंने कहा कि आज देश के युवाओं को एक सफल नेतृत्व की आवश्यकता है । और मुझे यकीन है कि विद्यार्थी परिषद् आज उस भूमिका को निभाने में सक्षम है । श्री आंबेकर ने प्रतिनिधियों से आव्हान किया कि वे देश के कोने–कोने से ऐसे युवा तैयार करें जो समाज और देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तत्पर रहे ।

समारोह के पश्चात वंदे मातरम् तथा ध्वजावतरण के साथ 53वें राष्ट्रीय अधिवेशन का समापन हुआ । ■

राष्ट्रीय अधिवेशन में प्रारित प्रस्ताव

प्रस्ताव–1

केन्द्र सरकार की दिग्भ्रमित उच्च शिक्षा नीति

देश में कुछ नये केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना की घोषणा तथा उच्च शिक्षा बजट में वृद्धि से केन्द्र सरकार के उच्च शिक्षा के प्रति सकारात्मक होने की प्रतीति होती है । परन्तु यथार्थ इसका ठीक उल्टा है । मानव संसाधन विकास मंत्री का देश के कुलपतियों के सम्मेलन में उच्च शिक्षा को बिमार बच्चा कहना इसकी स्थिति को उजागर करना है । संप्रग सरकार का उच्च शिक्षा के प्रति रवैया इतना गैर जिम्मेदाराना है कि आज यह तय करना कठिन हो गया है कि राष्ट्र की उच्च शिक्षा नीति के निर्धारण का दायित्व किसका है । प्रधानमंत्री, मानव संसाधन मंत्री, ज्ञान आयोग तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग समूची उच्च शिक्षा को चार अलग–अलग दिशाओं में खीचते हुए दिखाई दे रहे हैं । अभाविप का यह राष्ट्रीय अधिवेशन सरकार द्वारा उच्च शिक्षा के संबंध में अपनाई जा रही इस नीति की घोर निन्दा करता है ।

केन्द्र सरकार विशेषतया मानव संसाधन विकास मंत्रालय की सुस्त चाल एवं उपेक्षापूर्ण रवैये ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अनेक प्रकार की कुप्रवृत्तियों को बढ़ावा दिया है । विदेशी शिक्षण संस्थाओं के नियमन, विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में केन्द्रीय आदर्श ;डवकमसद्ध कानून सम्बन्धी बिल, निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों के लिए केन्द्रीय कानून, निजी विश्वविद्यालय बिल जैसे महत्वपूर्ण बिल लम्बित पडे हैं । इसका परिणाम है कि विदेशी शिक्षा संस्थाओं, निजी विश्वविद्यालयों तथा व्यावसायिक शिक्षा के विविध बाजारू उपक्रमों की अनियोजित बाढ़ सी आ गई है । राज्य सरकारें भी अपने राजनैतिक हित साधन की नीति के कारण इस सम्ब में कोई कडा कानून नही बना रही है । अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् का यह 53वाँ अधिवेशन मानव संसाधन विकास मंत्री की इस प्रकार की निष्क्रियता पर अपना क्षोभ व्यक्त करता है ।

उच्च शिक्षा में सुधार के लिए सीधे प्रधानमंत्री के अधीन में गठित ज्ञान आयोग ने उच्च शिक्षा में विस्तार, गुणवत्ता में सुधार, शैक्षिक प्रशासन को चुस्त–दुरूस्त करने तथा उच्च शिक्षा पर व्यय बढ़ाने जैसे विषयों पर विश्लेषण कर महत्त्वपूर्ण एवं स्वागत योग्य सुझाव दिये हैं, लेकिन यह अनुभव हो रहा है कि आयोग उच्च शिक्षा का समग्र चिंतन नहीं कर पाया है । केवल सूचना प्रोद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा पर ही विस्तार से विश्लेषण हुआ है । भाषा नीति, निजी कम्पनियों की शिक्षा में भागेदारी, विदेशी संस्थाओ के अपने देश की शिक्षा में प्रवेश के लिए एकल खिड़की योजना तथा उच्च शिक्षा तंत्र को संचालित करने के लिए वर्तमान में राष्ट्रीय उच्च शिक्षा संस्थानों को चुस्त–दुरूस्त करने के स्थान पर नये संस्थान खडे करने की अनुशंसाओं के सम्बन्ध में देश व्यापक बहस की आवश्यकता है । केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री उच्च शिक्षा की दुरावस्था को स्वीकार तो करते हैं, परन्तु सुधार पर कुछ भी नही कहते तथा ज्ञान आयोग की सुधारात्मक अनुशंसाओं पर भी मौन रहते हैं । ज्ञान आयोग एवं प्रधानमंत्री कार्यालय तथा योजना आयोग एवं मानव संसाधन मंत्रालयों द्वारा अलग–अलग प्रकार की प्राथमिकताओं की स्थिति पर अभाविप गम्भीर चिन्ता प्रकट करती है ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 11वी पंचवर्षीय

योजना से अल्पसंख्यक शिक्षा के लिये विशेष अनुदान के प्रावधान की केन्द्र सरकार की योजना से उच्च शिक्षा संस्थानों में अल्पसंख्यकवाद का बढ़ावा मिलेगा साथ ही अनुसूचित जाति, जन जाति तथा निर्बल वर्ग के लिये अनुदान की कमी होगी जो कि सामाजिक समरस्ता के लिए चिन्ताजनक तथा राष्ट्रीय एकता के लिये खतरनाक है । समग्र उच्च शिक्षा को गुणात्मक रूप से सुधारने के प्रयास, उच्च शिक्षा में विशेष कोचिंग योजना को अनिवार्य किये जाने से नकारात्मक रूप से प्रभावित होंगे । इस पंचवार्षिक योजना में शिक्षा क्षेत्र को कुल योजना व्यय का 19 प्रतिशत दिये जाने का स्वागतयोग्य निर्णय विकास की दृष्टि से अपर्याप्त सिद्ध होगा । क्योंकि इस राशि का एक बड़ा हिस्सा अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं के कथित विकास, छठे वेतन आयोग की अनुशंसाओं के अधीन वेतन भुगतान, विशेष भर्ती अभियान एवं कोचिंग पर व्यय हो जायेगा ।

गुणवत्ता विकास तथा उसका मूल्यांकन उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है । इस कार्य हेतु यू. जी.सी. द्वारा 1994 में राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (NAAC) की स्थापना की गयी थी । नैके के द्वारा मूल्यांकन की गति अत्यंत धीमी है अभी तक 56 प्रतिशत विश्वविद्यालयों तथा 26 प्रतिशत महाविद्यालयों का ही मूल्यांकन हुआ है । जो इस संस्था की सुस्त चाल को दर्शाता है । अभी तक की प्रणाली भी संदेहयुक्त है । नैक की पीअर टीम पर अनेक स्थानों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं । मूल्यांकन के बाद नैक की ग्रेडिंग तथा मूल्यांकित संस्था की समाज में प्रतिष्ठा के बीच स्थान–स्थान पर बड़ा अन्तर भी देखने मे आया है।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का यह राष्ट्रीय अधिवेशन शिक्षण संस्थानों को मूल्यांकन के लिये जागरूक होने की आवश्यकता के साथ ही साथ नैक से मूल्यांकन गति को तेज किये जाने की मांग करता है । परिषद के इस अधिवेशन का स्पष्ट मत है कि नैक की गति तेज करने के लिये इसके कार्यों को निजी एजेन्सी को दिया जाना उचित नही है क्योंकि इससे मूल्यांकन प्रक्रिया के बाद से बदतर होने तथा छात्रों के शोषण के हथियार बननेकी गंभीर आशंका से कोई इन्कार नही कर सकता । मूल्यांकन निहित स्वार्थो से प्रभावित न हो इसके लिये नैक द्वारा देशभर के शिक्षाविदों तथा प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों का सहयोग लेकर तटस्थ एवं व्यापक पहुंच वाली पारदर्शी रचना खडी करनी चाहिए ।

केन्द्र सरकार द्वारा शिक्षा को सेज (SEZ) की परिधि में लाने के प्रयासों का विद्यार्थी परिषद तीव्र विरोध करती है । सेज में शिक्षा को प्रारंभ करने का सीधा अर्थ शिक्षा का बाजारीकरण है । इसके साथ ही विदेशी शिक्षण संस्थानों को देश के विविध शैक्षिक अधिकरणों से बिना अनुमति, प्रमाणन या मान्यता के अपने शैक्षिक संस्थान खोलने का अवसर प्रदान करना भी है । सरकार का यह कदम शिक्षा का पूर्णतया बाजारीकरण कर देगा साथ ही साथ इसमें चलने वाले पाठ्यक्रमों पर कोई नियंत्रण न होने के कारण शिक्षा का अभारतीयकरण होगा तथा बाजार की मांग के अनुसार शिक्षा का स्वरूप मूल्यविहिन एवं लागत लाभ आधारित होना अवश्यंभावी है ।

उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्रसंघों की आवश्यकता पर चल रही बहस को माननीय उचतम न्यायालय के निर्णय से एक विराम लगा है । लिंगदोह समिति की अनुशंसाओं को स्वीकार करके उच्चतम न्यायालय ने सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्रसंघों की अनिवार्यता प्रतिपादित की है । किन्तु इस निर्णय को सरकार, विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों ने गंभीरता से नही लिया जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा छात्रसंघ निर्वाचन को प्रतिबंधित करना है । दिल्ली विश्वविद्यालय ने जिस प्रकार से समिति की अनुशंसाओं का अपनी सुविधानुसार उपयोग किया वह भी चिन्तित करने वाला तथ्य है । अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का यह राष्ट्रीय अधिवेशन मांग करता है कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय में प्रतिपादित विधि के आलोक में केन्द्र, राज्य सरकार तथा यू.जी.सी. द्वारा देशभर में छात्रसंघों का गठन प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से कराने के लिये कानून बनाकर सभी उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए बाध्यकारी किया जाये ।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का यह राष्ट्रीय अधिवेशन देश की उच्च शिक्षा के प्रति केन्द सरकार के दिशाभ्रम को लेकर चिन्तित है । परिषद इस बात से भी चिन्तित है कि जब सरकार को मालूम है कि उच्च शिक्षा बीमार है तो उसके इलाज के लिए आवश्यक उपाय करने के लिए तत्पर क्यों नही है ? केन्द्र सरकार के विभिन्न अधिकरणों के द्वारा उच्च शिक्षा को जिस प्रकार से अलग–अलग दिशा में चलाने की कोशिश की जा रही है उससे उच्च शिक्षा इस देश की आवश्यकता को पूरा करने में अक्षम साबित होगी । अतः अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 53वें राष्ट्रीय अधिवेशन का स्पष्ट एवं सुविचारित मत है कि शिक्षा से जुडे सभी विषयों पर विचार करने के लिए एक स्वतंत्र, तटस्थ एवं स्वायत्त राष्ट्रीय शैक्षिक पीठ की स्थापना की जाये और उसके निर्देशन में देश भर की शिक्षा व्यवस्था का संचालन किया जाये । ■

प्रस्ताव–2

वर्तमान परिदृश्य

देश का वर्तमान परिदृश्य आज चारों ओर से आतंकवाद, अल्पसंख्यकवाद तथा वामपंथी आतंक एवं नक्सलवाद के आक्रमण के साये में है । एक ओर देश की आन्तरिक एवं बाह्य सुरक्षा गम्भीर खतरे में है तो दूसरी ओर देश की एकता, अखण्डता, प्रभुता एवं राष्ट्रीय स्वाभिमान को कड़ी चुनौती दी गई है । ऐसे में पड़ोसी देशों के भीतर घट रहे घटनाक्रमों के कारण देश की सीमाओं पर कई प्रकार के खतरे बढ़े हैं । देश में बढ़ती आतंकवादी घटनाओं, नक्सलवादी हिंसा एवं नंदीग्राम में वामपंथियों द्वारा हत्याओं से निर्दोष एवं निरीह लोगों का खून लगातार बह रहा है जिस पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिशद् का यह 53वाँ राष्ट्रीय अधिवेशन गम्भीर चिन्ता व्यक्त करता है ।

एक ओर देश का वित्त मंत्री राष्ट्र के लिए अपमानजनक वक्तव्य देता है कि भारत एक कंगाल देश है, तो वहीं 1857 के 150 वर्ष पूर्ण होने पर संप्रग सरकार द्वारा अंग्रेजों को 1857 की क्रांति के स्मृति के स्थानों पर 'विजय दिवस' मनाने की अनुमति देना, भारत के स्वाभिमान को ललकारना है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का यह 53वाँ राष्ट्रीय अधिवेशन इसकी घोर निन्दा करता है ।

पड़ोसी देश पाकिस्तान में आपातकाल एवं हिंसा का तांडव, अनिश्चितता एवं अस्थिरता की स्थिति भारत के लिए चिन्ता का विषय है क्योंकि इन परिस्थितियों में आतंकी संगठन अपनी गतिविधियाँ तेज कर जम्मू–कश्मीर से लेकर देश की विभिन्न सीमाओं पर आतंक फैला सकते हैं । ऐसी परिस्थितियों में पाकिस्तान में परमाणु हथियार गलत हाथों में जाने को भी नकारा नही जा सकता । अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् का यह 53वाँ राष्ट्रीय अधिवेशन मांग करता है कि भारत जम्मू–कश्मीर के साथ–साथ देश की सीमाओं पर सुरक्षा कड़ी करते हुए परिस्थितियों पर अपनी नजर रखे।

देश में नक्सलवाद के नाम पर आतंकी घटनाएँ अपने चरम पर है । हाल ही में झारखण्ड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के पुत्र सहित 18 लोगों की चिल्खारी में नृशंस हत्या, छत्तीसगढ़ के बस्तर में कई पुलिस जवानो के साथ सैकड़ो निरीह लोगों को मौत के घाट उतारना, कर्नाटक में बस जलाकर चुनौती देना इस बात को सिद्ध करता है कि नक्सली समस्या आज देश के लिए गम्भीर चुनौती बनी है । लेकिन नक्सलियों के लगातार हिंसा के तांडव के खिलाफ केन्द्र व राज्य सरकारों की योजना पूरी तरह से विफल सिद्ध हो रही है । देश के प्रधानमंत्री तथा गृहमंत्री नक्सलवाद को देश के लिए गम्भीर खतरा तो बताते हैं लेकिन संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन (यू.पी.ए.) सरकार के प्रमुख घटक वामपंथी देश में नक्सलवादियों का खुला समर्थन कर देश को गुमराह करते हैं । अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् वामपंथियों के इस दोहरे चरित्र की कड़ी आलोचना करते हुए मांग करती है कि केन्द्र व राज्य सरकारें नक्सलवाद के खिलाफ प्रभावी कदम उठायें ।

24 नवम्बर को आसाम के गुवाहाटी में आदिवासी छात्र संगठन की रैली के बाद हुई घटना में निर्दोष एवं निहत्थे छात्र–छात्राओं पर असामाजिक तत्वों द्वारा हमला व छात्राओं को निर्वस्त्र कर घसीटे जाने की अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् कड़े शब्दो में निन्दा करता है, तथा इलेक्ट्रानिक मीडिया के कुछ चैनलो द्वारा उक्त दृश्य दिखाना दुर्भाग्यपूर्ण मानता है । अ.भा.वि.प. माँग करता है कि प्रेस काऊन्सिल ऐसे प्रसारणों पर तुरंत रोक लगाए । इस घटना की जांच के लिए पूर्व न्यायाधीश की आर.के. मनीसेना सिंह कमेटी से मांग करती है कि वह शीघ्र अपनी रिपोर्ट दे जिससे जनजाति समाज के विश्वास को बहाल किया जा सके व दोषियों को कड़ी सजा दी जा सके ।

देश में लगातार घट रही आतंकवादी विस्फोटों की घटनाओं के जख्म अभी भरे नही थे कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ, काशी एवं फैजाबाद के न्यायालय परिसर में श्रृखंलाबद्ध विस्फोट कर आतंकवादियों ने इस देश की सुरक्षा को कडी चुनौती दी है । देश की इन आतंकी घटनाओं मे बांग्लादेशी घुसपैठियों का प्रमुख तौर पर पाया जाना दर्शाता है कि घुसपैठिये देश के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक रूप से चुनौती ही नही बल्कि देश की सुरक्षा के लिए चुनौती बन रहे हैं । अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् का यह राष्ट्रीय अधिवेशन केन्द्र सरकार से मांग करता है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ व्यापक नीति बनाकर उन्हें देश के

बाहर करे ।

जम्मू में पढ़ने वाली पूंछ के एक संप्रदाय विशेष की छात्रा, जो एक सरकारी अधिकारी की पुत्री है, का हथियार सहित पकड़ा जाना, कश्मीर घाटी के एक वर्ग विशेष के परिवारों की आतंकवादियों के साथ संलिप्तता को दर्शाता है यह देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है ।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् का यह 53वाँ राष्ट्रीय अधिवेशन न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र की अध्यक्षता में बने राष्ट्रीय धार्मिक भाषाई अल्पसंख्यक आयोग की इस सिफारिश पर गम्भीर आपत्ति प्रकट करता है, जिसके अन्तर्गत केन्द्र सरकार धर्मान्तरित ईसाई व मुसलमानों को बड़ी तीव्रता से अनुसूचित जाति की श्रेणी में लाने का प्रयास कर रही है । तमिलनाडु एवं आन्ध्र प्रदेश में प्रदेश सरकारों द्वारा इन अल्पसंख्यकों को ओ. बी.सी. आरक्षण की सुविधा देना तुष्टिकरण की नीति का परिचायक है । अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् का यह राष्ट्रीय अधिवेशन मांग करता है कि अनुसूचित जाति के मंतातरित ईसाईयों एवं मुस्लिमों को आरक्षण की घोषणा तत्काल रद्द करें तथा तमिलनाडु एवं आन्ध्र प्रदेश की सरकारें भी अल्पसंख्यकों को प्रारंभ किये गये आरक्षण को समाप्त करें।

पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में मार्क्सवादियों के हिंसाचार से एक बार फिर मानवता सिसक उठी है । पिछले ग्यारह महीने से पश्चिम बंगाल की पुलिस के संरक्षण में माकपाई गुण्डों द्वारा रक्त रंजित इतिहास लिखकर लोकतन्त्र को कलंकित किया है । सैंकड़ों निरीह निर्दोष किसानों की हत्याएँ करने के बाद सन् 2001 के छोटा आंगरिया काण्ड की तरह ही मार्क्सवादियों ने अपने आतंक के द्वारा कम्युनिस्ट तानाशाह स्टालिन के निरंकुशता के युग की याद दिलाता है । लेकिन दुर्भाग्य का विषय यह है कि घटना के बाद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य द्वारा अपने माकपाई गुण्डो को यह कहते हुए निर्दोष बताया है कि नंदीग्राम के लोगों को उन्हीं की भाषा में ही माकपा कार्यकर्ताओं ने जवाब दिया है । यह पश्चिम बंगाल में माकपा शासन द्वारा कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का स्पष्ट संकेत है, जो भर्त्सनीय है । माकपा नेता प्रकाश करात द्वारा यह कहना कि यह घटनाऐं माओवादियों द्वारा की जा रही हैं, वामपंथियों के दोहरे चरित्र को फिर से उजागर करता है । एक और मार्क्सवादी नेता सीताराम येचुरी नेपाल जाकर माओवादियों के पक्षकार बनते हैं तो दूसरी और बस्तर में नक्सलवादियों के समर्थन मे रैली कर अपने राष्ट्रविरोधी चरित्र को उजागर करते हैं । अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का यह 53वाँ राष्ट्रीय अधिवेशन माँग करता है कि पश्चिम बंगाल की खूनी वामपंथी सरकार को तत्काल बर्खास्त कर दोषी वामपंथियों पर कड़ी कार्यवाही की जाये ।

पश्चिम बंगाल की वामपंथी सरकार द्वारा स्वतन्त्र लेखिका तसलीमा नसरीन को कट्टरपंथियों के दबाव में पं. बंगाल से बाहर निकालना, लोकतांत्रिक स्वतन्त्रता एवं पंथनिरपेक्षता के ऊपर कड़ा प्रहार है । अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करने वाले वामपंथी वोट की राजनीति के लिए मुस्लिम कट्टरता के पक्ष में खड़े हैं, जो अत्यंत निन्दनीय है । अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हुए मांग करता है कि स्वतंत्र लेखिका तसलीमा नसरीन को भारत में शरण दी जाए ।

अभाविप अपने इस 53 वे राष्ट्रीय अधिवेशन के माध्यम से देश की छात्र–शक्ति को आवाहन करता है कि वह देश के कमजोर एवं असहाय होते नेतृत्व पर चिंतन करें तथा देश हित में अपनी प्रभावी भूमिका का निर्वहन करते हुए विश्वविद्यालय, महाविद्यालय परिसरों में इन मुद्दों के बारे में बहस पैदा कर राष्ट्रहित में छात्र समुदाय को गोलबंद करें ।

अमेरिका के साथ हो रहे परमाणु समझौते के कारण देश आज अप्रत्याशित अनिश्चतता के दौर से गुजर रहा है। केन्द्र की सत्ता में बैठे संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यू.पी.ए) सरकार के सहयोगी वामपंथियों की ब्लैकमेलिंग एवं दबाव की राजनीति के कारण आज समाज के सामने प्रश्न खड़ा है कि आखिर इस देश की सरकार कौन चला रहा है ? परमाणु संधि से लेकर आतंकवाद, नक्सलवाद, नन्दीग्राम के नृशंस अत्याचार या देश के मानबिन्दुओं पर आक्रमण कर देश के नेतृत्व द्वारा चुप्पी साधना तथा देशद्रोही ताकतों के सामने घुटने टेकना देश की सम्प्रभुता एवं सुरक्षा के लिए गम्भीर चिन्ता का विषय है तथा यह सिद्ध करता है कि आज देश का नेतृत्व कमजोर हुआ है जो इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिये खतरा है । अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपने इस 53वे राष्ट्रीय अधिवेशन के माध्यम से देश की छात्र–शक्ति को आवाहन करता है कि वह देश के कमजोर एवं असहाय होते नेतृत्व पर चिंतन करें तथा देश हित में अपनी प्रभावी भूमिका का निर्वहन करते हुए विश्वविद्यालय, महाविद्यालय परिसरों में इन मुद्दों के बारे में बहस पैदा कर राष्ट्रहित में छात्र समुदाय को गोलबंद करें । ■

INTERNATIONAL SEMINAR AT NEW DELHI

"Don't Commercialise Education"

WOSY

World Organisation of Students and Youth (WOSY) organized two days international seminar on "Impact of globalization on education'on February 2-3,2008 in Viswa Yuva Kendra, New Delhi.

The international seminar which was attended by 114 students (20 girls) from 30 countries,which includes, Mauritius, Nepal, Afganistan, India, Tibet, Bhutan, Mangolia, Iran, Poland, Mozambique,Oman, Kenya,France, Tanzania, Germany, Japan, Vietnam, Laos, Uzbekistan, Iraq, Syria, Camroon, Bangladesh, Australia, Maldives, UK, Uganda,Guyana, Tazakistan. The semiar was inaugurated by H.E. Shri. Mookhesswar Choone, High Commissioner, Mauritius.In his inaugural address Shri.Mookhesswar Choone while appreciating the efforts of WOSY said that youth have extraordinary talent and they can give a new look to the world

Shri. Sushil Pandit, Chairman WOSY while addressing in the inaugural session laid down the aims and objectives of WOSY. He said that WOSY believes in one indivisible universe and is driven by the age-old Indian precept that 'world is one family'. WOSY manifests in the promotion of this motto through various activities among the youth, which are entirely for the youth by the youth and of the youth. Welcome speech was delivered by Prof. Bharat Bhushan, President WOSY Delhi .

Prof.K.B.Powar, former Secretary. Genenaral of Association of Indian Universities was the key speaker in the inaugural session .He stated "The term globalization was originally used for the process of increasing convergence and independence of state economies. In the broder sence globalization refers to the flow of capital, people,culture, knowledge , technology and values a cross national borgers resulting in a more inter-connected, more inter-dependent and less diverse world but trade in Education Services covers initiatives in delivery of education which are commercial in nature and are intended for generation of profit.Inclusion of education as service under GATS drew strong reaction from academic circles. A joint declaration on higher education and GATS,adopted by four major organizations of North America, and Europe, and endorsed by the International Association of Universities , stated: "Higher Education exists to serve the community and is not a commodity.

Prof.Milind Marathe ,HOD,Somaya Eng.college,Mumbai,in his key note address said'while the rapid pace of globalization is not only shrinking the distance and turning the world in to a virtual "global villege" but the inclusion of education as a tradable commodity in the GATS has radically changed the perception of education as a core component of individual and national life. While technological advanced has turned education into a tool for human being for the material advancement of a positive, philosophical and humane social system.

The commercialization of education; impact of bringing education under GATS. Dr. Dayanad Dongoankar was chief speaker for this session. He pointed out the number of international students studying in India and USA, and European countries. He also talked about the preference for the courses in the different country. He mentioned in his speech that privatization of education with some restrictions of government is possible.But if commercialization of education takes place it keeps away poor or economically backward classes form education so it might be harmful in the education field. Prof. Dayanad Dongonkar further said that education is a process of acquiringand inheriting the knowledge base across generation. In the history education was a means of imparting the value and knowledge system into knowledge Economy leading to commercialization of education. Here commercialization Refers to making an excessive or unfair profit, essentially making educationas a product in a consumer market. The session was presided by J. L. Azad who was former chief of education division of NIEPA, Delhi. In conclusion of the session he said that the people should be awared about the rank of foreign universities which are running there operations in the different country. They must be aware about quality of education provide by that universities.

In the session "The Impact of Globalization on culture, moral values, chief speaker Prof. Kapil kapoor (Ex Pro. VC JNU) stated that under the name of globalization people follow the nation who are having money and power and the are losing there culture because of it. He also mentioned that people losing there traditions because of the globalization. "there ware civilization that focused on the mind, such as the Greeks, civilization that focused on so conduct such as the Confucian Chinese, and civilization that on the self, such as the ancient Hindu. The contemporary is built around the stomach- let us hope it will move away from that".

The third and most interactive session was the impact of globalization on student activism. Where Mr. Ramesh pappa sec, general of WOSY gave evidences how student activism have important role in the history of different nations., Globalisation has made wide impact on society and offcourse it has also affected student activism. Students have always played their role either in freedom struggle or in nation building through constructive activities. Students in many countries successfully agitated to throw out dictatorial or anti-people political regimes.In the era globalization student activism is continued to play its adding new dimensions to face consequences of Globalisation. Prof.Rajkumar Bhatia, founder member of WOSY,while presiding over the session said that youth are present citizens and have to play important in making the world a better place to live and there should not be any move to discourage their activisim on the name of globalization spoke about the history of student activism in India. How it work during the emergency in India. How it cause for the change for ruling government of India.

Prof. J.S.Rajput (former Director. NCERT) who was chief speaker in the concluding session

in his address stated 'education is undergoing constant changes under the effect of globalization. It is ,therefore,necessary that each country should decide about the nature and extent of globalization that can be constructively introduced in their socio-economic systems.'

Shri.Sunil Ambekar,ABVP All India Organising Secretary, in his concluding address said "India as an ancient civilization is not not new to globalization on education i.e.knowledge. Since time immemorial, Indian preachers have interacted with the world, mutually benefiting both. But the 90's of the last century have been a decade of transition during which education systems have witnessed paradigm shift.

Meanwhile, Sh.Sushil Pandit, Chairman, WOSY nominated the names to the WOSY Central Committee which includes , Jasem from Iran, Ahmed from IRAQ, Leki and Kinelay from Bhutan,Munab from Bangladesh, M.S.Chaitra from India, Moru from Mozambique, Yvonne from Kenya, Abhishek from India, Dr.Rajneesh from India, Sandreen from Mauritius, Riaz from Afganistan,Sandeep Rana from Nepal,

Meeting of the newly formed WOSY Central Council was also held on this occasion. Sh.Ramesh Pappa, Secretary General of WOSY welcomed the new members of WCC, dicussed about proposed 3rd international WOSY conference sheduled to be held at next year in Delhi.and about WOSY helpline for the benefit of foreign students. It was also decided to hold the meeting of WCC in August / September 2008. ■

संस्था परिचय

बाल सदन : बच्चों का आदर्श आशियाना

लखनऊ स्थित बाल सदन के बच्चों के मुख से वेद और उपनिषद् के मंत्रों का धाराप्रवाह उच्चारण सुन कोई भी दांतों तले अंगुली दबाने को मजबूर हो जाएगा। यहा वैदिक शिक्षा के अलावा परपरागत स्कूली शिक्षा भी दी जाती है, लेकिन भ्रष्टाचार के चलते तमाम कोशिशों के बावजूद मान्यता से महरूम है स्कूल। सदन के सर्वेसर्वा श्री धर्मदत्त श्रीवास्तव गरीब और अनाथ बच्चों के लिए किसी मसीहा से कम नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने बेसहारा बच्चों को जीने का एक मकसद दिया है।

अक्सर यह बात कही जाती है कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं, यह कहने वाले तो बहुत मिल जाते हैं। लेकिन देश का भविष्य कहे जाने वाले वही बच्चे जब निराश्रित और तिरस्कृत जीवन जी रहे होते हो, तो शायद ही कोई ऐसा होता है जो उन बच्चों का सहारा बनने की पहल करे। लेकिन धर्मदत्त श्रीवास्तव जैसे चंद लोग ऐसे भी हैं जो सैकडो गरीब और अनाथ बच्चों को अपने परिवार का सदस्य मानकर उनके लालन–पालन में लगे रहते। उनके इस ध्येय को सार्थक करने मे उनके साथ उनकी पत्नी ओमेश्वरी देवी भी पूरा सहयोग देती हैं।

स्वामी निर्भयानंद द्वारा 1915 में स्थापित लखनऊ स्थित दयानन्द बाल सदन 15 बीघे जमीन में फैला हुआ है। जब धर्मदत्त जी ने बाल सदन की कमान संभाली और यहां का कायाकल्प करने मे जुट गए तो वे कई लोगों की आंखो में खटकने लगे क्योंकि वर्षों से वे लोग उस जमीन पर कब्जा किए हुए बैठे थे। धर्मदत्त जी ने जब यहां निर्माण कार्य करवाने शुरू करवा दिए तो उन्हें कई बार धमकियां मिली और उनकी हत्या का भी प्रयास हुआ लेकिन वे विचलित नहीं हुए। कई जानलेवा हमले होने के बावजूद भी धर्मदत्त जी की प्रतिबद्धता को न डिगा सकी और बच्चों के प्रति उनका लगाव अनवरत् जारी है। बाल सदन के सचिव श्री धर्मदत्त

1990 में उ.प्र. विद्युत परिषद् से सेवानिवृत हुए, तब से ही उन्होंने यहां आना शुरू किया और यहीं के होकर रह गए। उन्होंने जब यहां की कमान संभाली थी तो यहां मात्र 25 बच्चे हुआ करते थे लेकिन आज यहां 4 वर्ष से लेकर लेकर 16 वर्ष तक के करीब डेढ़ सौ बच्चे रहते हैं। बाल सदन के सचिव से अधिक वे बच्चों के अभिभावक हैं और पूरे बाल सदन की देखरेख उन्हीं के हाथ में है। यह उनकी प्रतिबद्धता और बच्चों के प्रति उनका लगाव ही था, जिसने श्रीमददयानन्द बाल सदन का पुनरोद्धार कर उसे नई पहचान दिलाई है। धर्मदत्त जी के नियमित रूप से कार्यभार संभालने से पूर्व यहां मात्र दो कमरे हुआ करते थे और भोजन की भी कभी-कभी बच्चों के लिए समस्या हो जाया करती थी।

एक समय था जब खुले आकाश के नीचे यहां खाना बनता था और वहीं पर बच्चे भोजन ग्रहण करते थे। लेकिन आज बाल सदन के बदले हुए स्वरूप को देखकर कोई यह नहीं कह सकता कि यह वही स्थान है जो कभी वीरान पड़ा रहता था। एक समय था जब सारी प्राथमिकताएं सिर्फ बच्चों को भोजन उपलब्ध करवाने तक ही सीमित थी। लेकिन धर्मदत्त जी का व्यापक दृष्टिकोण ही था जिससे उन्हें बच्चों में संस्कारयुक्त शिक्षा देने की सूझी और उन्होंने यहां बाल सदन का पूरा स्वरूप ही बदल डाला। इसी का परिणाम है कि आज यहां स्कूल, पुस्तकालय, यज्ञशाला, बच्चों के रहने के कमरे, डाइनिंग रूम, आडिटोरियम आदि सब कुछ है। संस्कार और अनुशासन तो यहां हर बच्चे में कूट कूट कर भरा हुआ है। सुबह साढ़े चार बजे से ही यहां बच्चों की दिनचर्या शुरू हो जाती है। स्नानादि करने के पश्चात् बच्चे यज्ञशाला में एकत्रित हो एक साथ यज्ञ करते है।

धर्मदत्त जी का कहना कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पढ़ाई के साथ-साथ खेलकूद, धर्म-कार्य इत्यादि की शिक्षा देना भी अनिवार्य है। बाल सदन के बच्चों के मुख से वेद और उपनिषद् के मंत्रों का धाराप्रवाह उच्चारण सुनकर कोई भी दांतों तले अंगुली दबाने को मजबूर हो जाएगा। यहां वैदिक शिक्षा के अलावा परंपरागत स्कूली शिक्षा भी प्रदान की जाती है। बाल सदन में ही कक्षा दस तक का स्कूल है, जिसमें दस अध्यापिकाएं हैं। स्वयं धर्मदत्त जी एवं उनकी पत्नी ओमेश्री देवी भी बच्चों को पढ़ाते हैं। बच्चों को वर्तमान परिवेश से जोड़ने के लिए उन्हें अंग्रजी तो सिखाई ही जा रही है साथ ही कम्प्यूटर की शिक्षा भी उन्हें दी जा रही है। पुस्तकालय में वेद, रामायण जैसी धार्मिक पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य विषयों की पुस्तकें भी बहुतायत में मौजूद है। तमाम तरह की बीमारियों से निजात दिलाने के लिए यहां मैग्नेटिक थैरेपी से बिना दवा के बच्चों का इलाज करने के लिए यहां चिकित्सालय भी मौजूद है। सब्जियों के भंडारण के लिए यहां देशी पद्धति से एक अंडरग्राउंड कोल्ड-स्टोरेज का भी निर्माण किया गया है। बच्चों के लिए दूध कितना आवश्यक है हम सभी जानते हैं, इसी बात को ध्यान में रखते हुए यहां एक गौशाला की भी व्यवस्था है, जिसमें करीब बीस गायें मौजूद हैं। भोजन बनाने के लिए यहां एक व्यवस्थित रसोईघर है। सभी बच्चों का पूरा रिकार्ड भी यहां मौजूद है जिससे कभी जरूरत पड़े तो पेश किया जा सके। भोजन बनाने के लिए रसोइये के साथ बच्चे भी सहयोग करते हैं। यही नहीं यहां के बच्चे अपने प्रत्येक कार्य को भली भांति समझते हैं। सदन के रखरखाव और संचालन में बच्चे यथोचित सहयोग करते हैं। बच्चों को दिए गए वेदों का ज्ञान और संस्कार ही हैं कि उन्हें दूर दूर के लोग विभिन्न कर्मकाण्डों में बुलाते हैं। यहां विभिन्न जाति और धर्मों के बच्चे रहते हैं। धर्मदत्त जी कहते हैं कि बच्चे भगवान का रूप हैं और जाति एवं धर्म के नाम पर किसी तरह का भेदभाव परमात्मा का अपमान है। उम्र के 70 पड़ाव पार कर चुका यह दम्पति बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने को ही अपनी संतुष्टि का आधार मानता है। परंतु एक बात की कसक धर्मदत्त जी को हमेशा बनी रहती है कि तमाम मंत्री एवं नेता लोग यहां के बच्चों की तारीफ तो कर चुके हैं लेकिन जब मदद करने कि बात आती है तो वे पल्ला झाड़ लेते हैं। वे कहते हैं कि तमाम मशक्कतों के बाद भी बमुश्किल पांचवी तक ही मान्यता मिल पाई है, हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे आगे पढ़ें लेकिन बड़े ही खेद के साथ वे बताते हैं कि स्कूल को आगे की मान्यता दिलाने के लिए अफसरों की जेब गरम करनी पड़ेगी, जो हम नहीं कर सकते क्योंकि यदि हम भ्रष्ट अधिकारियों की जेबे गरम करेंगे तो बच्चों को क्या खिलाएंगे। इतने पर भी वे निराशा का भाव अपने चेहरे पर झलकने नहीं देते और बच्चों को आने वाले कल की बुनियाद मानकर निरंतर अपना ध्यान बच्चों को अनुशासित वातावरण प्रदान करने में लगे रहते हैं जिससे उन्हें समाज का आत्मनिर्भर और जिम्मेदार नागरिक बनाया जा सके। ■

सवालों के घेरे में देवबंद की नियत

– आशुतोष भटनागर –

25 फरवरी को देश ने भारत की दूसरी सबसे बड़ी आबादी, मुस्लिम समुदाय के विषय में समानान्तर किन्तु परस्पर विपरीत चित्र देखे। संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल जहां सरकार की नीतियों को स्पष्ट करते हुए अल्पसंख्यक समुदाय के हित सुनिश्चित करने के लिये अनेक योजनाओं पर प्रकाश डाल रही थी वहीं दारुल उलूम देवबंद में सरकारी जांच एजेंसियों पर बेकसूर मुसलमानों को बलि का बकरा बनाये जाने का आरोप लगाते हुए सरकार को चेतावनी जारी की जा रही थी।

श्रीमती पाटिल ने अपने लिखित भाषण में कहा कि मेरी सरकार द्वारा प्रारंभ किये गये प्रधानमंत्री के नये पंद्रह सूत्री कार्यक्रम का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि विकास कार्यक्रमों का लाभ अल्पसंख्यकों को समतापूर्वक मिले। निर्दिष्ट अनुपात में विकास परियोजनाएं अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में स्थित होंगी और जहां संभव होगा, विभिन्न स्कीमों के तहत उद्देश्यों और परिव्ययों का 15 प्रतिशत अल्पसंख्यकों के लिये विनिर्दिष्ट होगा। अल्पसंख्यकों की आर्थिक और शैक्षिक स्थिति सुधारने के लिये सच्चर समिति की रिपोर्ट में की गयी सिफारिशों के आधार पर कई कार्यक्रम शुरू किये गये हैं।

पिछले कुछ समय में भारत सहित अनेक देशों में हुई आतंकवादी घटनाओं में भारतीय युवक लिप्त पाये गये हैं, गिरतार हुए हैं, मुठभेड़ में मारे गये हैं । सम्मेलन में यदि उनकी संलिप्तता की स्पष्ट रूप से निन्दा की जाती तो निश्चय ही अन्य भारतीय युवकों को भी आतंकवाद से दूर रहने की प्रेरणा मिलती। इसी प्रकार भारत में दो दशकों से भी अधिक समय से जारी आतंकवादी गतिविधियों में मुस्लिम समाज के भारतीय युवकों की संलिप्तता पर परदा डालने के बजाय उन्हें आतंक का रास्ता छोड़ कर समाज की मुख्य धारा में शामिल होने का आह्वान किया जाता तो भी यह सम्मेलन सार्थक हो सकता था।

11 वीं योजना में पेशेवर पाठ्यक्रमों के लिये योग्यता–सह–साधन पर आधारित छात्रवृत्ति के लिये 800 करोड़ रुपये, अल्पसंख्यक छात्रों के लिये मैट्रिक–पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति कार्यक्रमों के लिये लगभग 3300 करोड़ रुपये और 90 अल्पसंख्यक बहुल जिलों के विकास के लिये 3780 करोड़ रुपये का प्रावधान है। अल्पसंख्यक समुदायों को दिये जाने वाले प्राथमिकता क्षेत्र ऋणों के अनुपात को वर्तमान 9 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया जायेगा।

देश की मुखिया जब अल्पसंख्यक समुदाय की बेहतरी के लिये घोषणाओं का अंबार लगा रहीं थीं और विवादित सच्चार कमेटी की रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू किये जाने की घोषणा कर रहीं थीं ठीक उसी समय दिल्ली से दो सौ कि मी दूर स्थित उत्तर प्रदेश के देवबंद मे दारुल उलूम परिसर में आयोजित किये गये अखिल भारतीय आतंकवाद विरोधी सम्मेलन में शामिल उलेमा और मुस्लिम बुद्धिजीवी मुसलमानों को दहशतगर्द साबित करने की सरकार की कोशिशों की आलोचना कर रहे थे। सम्मेलन मे कहा गया कि सरकार मुसलमानों पर छाये संदेह के बादल को छांटने के बजाय अपनी एजेंसियों के जरिये उन्हें दहशतगर्द और मदरसों को आतंकवाद के अड्डे साबित करने की मुहिम छेड़े हुए है। वक्ताओं ने कहा कि मुसलमानों के साथ सरकार का रवैया पारदर्शी और न्यायपरक नहीं है ।

आतंकवाद के नाम पर निर्दोष मुस्लिम युवाओं को जेल में बंद किया जा रहा है। सम्मेलन में सरकारी मशीनरी के पक्षपातपूर्ण रवैये के खिलाफ मुहिम चलाने का प्रस्ताव भी पारित किया गया।

दारुल उलूम देवबंद का न केवल भारत के बल्कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुस्लिम समाज के बीच महत्वपूर्ण स्थान है बल्कि पिछले डेढ़ सौ वर्षों से लगातार वह भारत की मुस्लिम राजनीति को भी गहरे तक प्रभावित करता रहा है। यहां सोमवार को बुलाये गये इस सम्मेलन में अहले हदीस, जमीयत उलेमा ए हिंद, जमात ए इस्लामी, फिरंगी महली, जामिया सलफिया, ऑल इंडिया मिल्ली कोंसिल और ऑल इंडिया तंजीम उलेमा ए हिंद समेत पूरे भारत से मसलतों और तंजीमों के उलेमाओं ने भाग लिया। देश भर के मदरसों के हजारों विद्यार्थी भी इस मौके पर मौजूद थे।

इजलास में दूर-दूर से आये हजारों मुसलमानों को हाथ उठा कर आतंक के खिलाफ लडने की कसम दिलायी गयी। प्राय: ऐसे सभी सम्मेलनों में होने वाले इस प्रकार संकल्प लेने के कर्मकांड को छोड़ दिया जाय तो यह साफ महसूस किया जा सकता है कि आतंकवाद के विरुद्ध बुलाये गये इस सम्मेलन का उपयोग यह साबित करने की कोशिश में किया गया कि इस्लाम का दहशतगर्दी से कोई रिश्ता नहीं है।

हाथ उठा कर आतंकवाद के विरुद्ध किये गये संकल्प का निश्चित तौर पर स्वागत किया जाना चाहिये, आयोजकों की नियत पर भी शक करने का कोई कारण नहीं बनता, लेकिन अगर कुछ महीने पहले एक समाचार चैनल पर इसी देवबंद के मौलवियों द्वारा पैसे लेकर फतवा जारी करने की बात भूल भी जायें तो भी यह सवाल जरूर उठता है कि गुडिया और इमराना जैसे छोटे-छोटे मामलों में भी फतवा जारी करने वाले दारुल उलूम देवबंद ने आतंकवाद के खिलाफ अपने आपको केवल घोषणा तक सीमित रखा, फतवा जारी करने की जहमत नहीं उठाई।

आतंक के खिलाफ फतवा न जारी किये जाने के निहितार्थ क्या है ? सम्मेलन के साधारण चर्चा तक सीमित होने का तर्क इसलिये नहीं चल सकता क्योंकि सरकारी एजेंसियों पर हमला करते समय वक्ताओं ने गहराई से छिद्रान्वेषण किया, कड़े शब्दों में चेतावनी दी। आतंकवाद के खिलाफ बुलाये गये सम्मेलन का इस्तेमाल आतंकवादियों की निन्दा से अधिक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर हमला करने और हाल ही में एक पत्रकार द्वारा लिखी गयी किताब 'इस्लामी मदरसे बेनकाब' में मदरसों पर की गयी टिप्पणियों का जबाब देने में किया गया। यहां तक कि नाथूराम गोडसे को आर एस एस का कार्यकर्ता और पहला आतंकवादी बताया गया।

मौलाना मुती फिरंगी महल ने कहा कि मदरसों का नाम आतंकवाद से इसलिये जोड़ा जा रहा है ताकि इस्लाम के बढ़ते कदम और मुसलमानों की तरक्की को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि जिन शहरों में मुसलमानों ने कारोबार विकसित किये वहां दंगे कराये गये। इसके बावजूद मुसलमान डॉक्टर और इंजीनियर बनने लगे तो उन्हें आतंकवादी करार देने की साजिश रची जा रही है। सवाल उठता है कि सम्मेलन से उठने वाले यह कमजोर स्वर क्या दुनियां भर में सिर उठा रहे आतंकवाद के खिलाफ कोई निर्णायक चुनौती प्रस्तुत कर सकेंगे एक राजनैतिक दल के राज्यसभा सदस्य द्वारा सम्मेलन के मंच का उपयोग यदि दूसरे राजनैतिक दल पर प्रहार करने के लिये किया गया तो इसका मकसद वर्ष के अंत तक संभावित आमचुनाव के मद्देनजर देश में मुस्लिम वोट बैंक को मजबूत करने का अधिक दिखता है और विश्व व्यापी आतंकवाद की चुनौती के खिलाफ खड़े होने का कम।

पिछले कुछ समय में भारत सहित अनेक देशों में हुई आतंकवादी घटनाओं में भारतीय युवक लिप्त पाये गये हैं, गिरफ्तार हुए हैं, मुठभेड में मारे गये हैं । सम्मेलन में यदि उनकी संलिप्तता की स्पष्ट रूप से निन्दा की जाती तो निश्चय ही अन्य भारतीय युवकों को भी आतंकवाद से दूर रहने की प्रेरणा मिलती। इसी प्रकार भारत में दो दशकों से भी अधिक समय से जारी आतंकवादी गतिविधियों में मुस्लिम समाज के भारतीय युवकों की संलिप्तता पर परदा डालने के बजाय उन्हें आतंक का रास्ता छोड़ कर समाज की मुख्य धारा में शामिल होने का आह्वान किया जाता तो भी यह सम्मेलन सार्थक हो सकता था। कश्मीरी पंडितों की घरवापसी की बात भी अगर पारित प्रस्ताव में शामिल होती तो राष्ट्रीय एकता को निश्चय ही बल मिलता।

इसके अभाव में भी मीडिया में जिस तरह से आतंकवाद के खिलाफ सम्मेलन की कागजी घोषणा को, जो फतवा न होने के कारण सम्मेलन में मौजूद लोगों पर भी बाध्यकारी नहीं है, एक नयी क्रांति के रूप में प्रस्तुत किया गया उसे या तो प्रायोजित मानना होगा अथवा मीडिया की हवाई कल्पना, जिसमें वास्तविकता के रंग भरना कठिन ही नहीं नामुमकिन है। ■

Marxist Attack on Student Learder in Kerala

On February 28, C S Sanoop, a BSC final year student of Guruvayur Sri Krishna College in Kerala was brutally attacked with iron rods by a group of SFI and Marxist goons. Such was the cruelty that Sanoop's left eye ball popped out through the injury caused in the attack. According to Dr Thomas Cherian, head of the department, Ophthalmology at the Little Flower hospital where he was admitted, the student had lost his vision when he was brought in. The assailants also broke Sanoop's left leg with iron rods.

Marxist outfits had been ruling the college in their true Stalinist style since long. Any voice of dissent was muzzled and those who dared to challenge their autocracy were physically eliminated.

During the last college union elections held in November 2007, Sanoop decided to dare the Marxist fascism and contested to the post of Chairman from the ABVP panel. The boy who was excellent in his studies struck an instant rapport with the students and won the election by a considerable margin.

Sanoop's victory stunned the Marxists as they felt that they were loosing grip on the college. As is the case in every SFI-ruled college in Kerala, the Marxists decided that they would not allow any one else to enter what they hold as their fiefdom. Having failed ideologically, they planned to physically confront Sanoop.

After the election results were announced, the SFI cadres locked up Sanoop in the class and assaulted him. Finally, he was released only after police intervened. Keeping up their offensive, they carefully schemed to deny him permission to swear in as the College Union Chairman.

On February 28, Sanoop, had gone to the college to write the first year improvement exam. He was a brilliant student and was not satisfied with the marks he got for the first year exam and wanted to improve it. The Marxists decided to take use of this and walked into the examination hall armed with iron rods. Sanoop was beaten black and blue by the criminals who then escaped from the scene. Finally it was the teachers who shifted him to the hospital.

Sanoop is the only son of his parents. His father earns livelihood by making and selling cheap furniture. He is an excellent orator too.

Police has registered a case against 6 SFI activists who are said to be absconding. According to information, the attackers are not only SFI activists, but active cadres of the ultra-Islamic National Democratic Front (NDF). NDF role is suspected in many anti - national activities including the 2003 Marad massacre wherein 8 Hindu fishermen were bludgeoned to death in their sleep on the Marad beach in Kozhikode district. NDF, which is controlled by Wahabi elements, has infiltrated outfits like the SFI and CPM as they realize that they cannot achieve their ends by fighting alone. They plant moles in these outfits who then double up as cadre for jihad. ■

जरूरत है, मामले की गंभीरता को समझने की

– आशीष कुमार 'अंशु' –

बात त्रिपुरा के पूर्व डीजीपी बलजीत राय की पुस्तक 'डेमोग्राफीक एग्रेशन ऑफ इडिया' से शुरु करते हैं। जिसके अनुसार आज के समय में बांग्लादेश और भारत की सीमा की पहचान सीमा के तौर पर करना मुश्किल है। आज एक अनुमान के अनुसार भारत में डेढ करोड बांग्लादेशी घुस आए हैं। इसकी एक मात्र वजह समाज में जागरूकता की कमी है। समस्या विकट हो चुकी है और सरकार को समाधान नहीं सुझ रहा। वैसे घुसपैठियों को बाहर निकालने की मुश्किल इतनी बडी भी नही है, जिसे इतना बडा हौव्वा बना दिया गया है। इनकी पहचान आसानी के साथ की जा सकती है और इन्हें बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है। लेकिन हम हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। किसी बड़ी दुर्घटना के इंतजार में। इस देश के राजनीतिक हों अथवा सरकारी मुलाजिम, जब तक कोई बडी दुर्घटना नहीं हो जाती, तब तक वे मामले की गंभीरता को नहीं समझ पाते। बांग्लादेश की सीमा से लौटे युवा पत्रकार मयंक जैन के अनुसार– 'अगर हम नहीं संभले तो, स्थिति दुबारा विभाजन की है।' जैन ने अपनी एक डोक्यूमेन्टरी फिल्म में बांग्लादेश की समस्या को सुंदर ढंग से समाज के सामने रखा है।

'बोर्डर मैनेजमेन्ट टास्क फोर्स' की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग दो करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठ कर चुके हैं। एक गैरसरकारी रिपोर्ट के अनुसार बंगाल, बिहार और पूर्वोत्तर के राज्यों में स्थिति बहुत नाजुक है। यदि जल्दी इस पर काबू नहीं पाया गया तो हालात बिगड़ सकते हैं। यदि हम बांग्लादेश के ही एक अखबार 'द मॉर्निंग सन' की माने तो 1981–91 के बीच बांग्लादेश से लगभग एक करोड़ लोग लापता हैं। यह कहां गए इसकी कोई जानकारी नहीं है। वहीं बांग्लादेश जनसांख्यिकी विभाग की शरीफा बेगम के अनुसार बांग्लादेश से अब तक गायब होने वालों की संख्या एक करोड़ चालीस लाख के करीब है। असम के ग्यारह जिलों में बांग्लादेशी नागरीकों की बढ़ती संख्या चिन्ताजनक है। डोगरी में यह संख्या जहां 74 फीसदी पर पहुंच चुका है। वहीं किशनगंज में बांग्लादेशियों की संख्या 66 फीसदी हो चुकी है। बारपेटा और मारीगांव जैसे असम के अंदर के गांवों पर भी धीरे–धीरे बांग्लादेशियों का कब्जा होता जा रहा है। वे आदिवासियों की जमीन औने–पौने दाम पर खरीद रहे हैं।

पूर्वोत्तर और पश्चिम बंगाल के चालीस हजार नौ सौ दस स्क्वायर किलोमीटर के शरहदी ,बोर्डरद्ध इलाके में 90 फीसदी बांग्लादेशियों का कब्जा है। नादिया जिले में तो बांग्लादेशी जमकर चरस की खेती कर रहे हैं और उससे जो पैसा मिलता है, उससे माओवादियो की मदद करते हैं। बड़ी तादाद में ऐसे बांग्लादेशी भी इस देश में रह रहे हैं, जिन्होंने राशन कार्ड बनवा रखा है, उनके पास वोटर आई कार्ड भी है। जब एक पत्रकार ने बांग्लादेशियों के घुसपैठ से संबधित एक सवाल सीपीआई नेता एबी बर्धन से पूछा तो वे भड़क गए– क्या भारत के लोग बाहर नहीं जाते, फिर बांग्लादेशियों के प्रवेश से कौन सी आफत आ रही है?

अब उन्हें कौन समझाए कि भारत के लोग जो बाहर जाते हैं, उनके साथ उनका पासपोर्ट भी होता है, और वीजा भी। वे किसी देश में छुप के घुसपैठीए की तरह नहीं जाते। भारत की नागरिकता ले चुके एक बांग्लादेशी ने बताया कि बांग्लादेश से भारत आना बेहद आसान है, सिर्फ पन्द्रह सौ रुपया खर्च करना होता है, बिना पासपोर्ट और वीजा के, उनके देश में सक्रिय दलाल उन्हें मुम्बई तक छोड़ कर जाता है। बलजीत राय के अनुसार अब पूर्वोत्तर के राज्यों में एक नए समुदाय का जन्म हो रहा है, जिसका नाम है सीमइया। सीमइया बांग्लादेशी लड़के और क्रिश्चियन लड़की की शादी के बाद पैदा हुए बच्चों का समुदाय है। जिसमें मां क्रिश्चियन होती है और बाप बांग्लादेशी। गोहाटी विश्वविद्यालय के प्राध्यापक दीपांकर बनर्जी के अनुसार पश्चिम बंगाल के 20 फीसदी सीटों और असम के 33 फीसदी सीटों पर बांग्लाशी निर्णय को प्रभावित करने वाली संख्या में पहुंच चुके हैं। यदि आज उनके लोग भी संसद में पहुंच रहे हों तो बड़ आश्चर्य की बात नहीं होगी। असम के डुमरी में बांग्लादेशी बच्चों को आईएएस बनाने की तैयारी करवाई जा रही है। उनके लिए कोचिंग सेन्टर खोले गए हैं। इस तरह भारत की राजनीति और प्रशासन दोनों जगहों पर वे अपने लोगों को फीट करने के चक्कर में हैं। यदि आज हम इस बात की गंभीरता को नहीं समझेंगे तो कल काफी देर हो जाएगी। हमें जागना होगा। कुछ घुसपैठीए बांग्लादेशियों को उस तरह की सजा मिलनी चाहिए जो अन्य बांग्लादेशियों के लिए सबक बन जाए और वे घुसपैठ की सोचे ही ना। ■

पश्चिम में घुलती हिंदी भाषा

अक्सर कहा जाता है कि हिन्दी को उपेक्षित नजरों से देखा जाता है। लेकिन इस तरह की बातें तब बेमानी सी जान पड़ती है, जब विदेशों में हिन्दी भाषा के परचम लहराने की खबरों से हम रू–ब–रू होते हैं। आज अनेक विदेशी विश्वविद्यालयों में हिन्दी की शिक्षा दी जा रही है, जिसको लेकर गजब का उत्साह देखने को मिला है। इन संस्थानों में विदेशी छात्रों का रुझान भी बढ़ा है। ऐसे में यह सवाल कि हिन्दी का प्रचार प्रसार नहीं हो पा रहा है, कितना सही है? परिचर्चा के माध्यम से जानने की कोशिश की है अवधेश कुमार मलिक ने –

जपनीत कौर,आई.पी. यूनीवर्सिटी, दिल्ली

पश्चिमी मुल्कों मे हिंदी सीखने व जानने वालों की तादाद बढ़ती ही जा रही है। इसके कई कारण हो सकते हैं जिनमें प्रमुख है। विदेशों में भारतीयों की अधिकता। पैसे कमाने व बेहतर भविष्य के लिए भारतीय वर्षों से विदेश जाते रहे हैं। आई.टी. बूम के बाद इस क्षेत्र में काफी तेजी देखने को मिली है। लेकिन, सबसे बड़ी बात यह है कि अधिकांश भारतीय विदेशी नागरिकता प्राप्त कर लेने के बाद भी अपनी संस्कृति को नहीं भूलते। विदेशों में भारतीय जब भी मिलते हैं तो अपनेपन के अहसास के लिए वो ज्यादा से ज्यादा अपनी भारतीय भाषा हिंदी का प्रयोग करते हैं। वहां रहकर भी वे अपने त्यौहारों को उसी प्रकार से मनाते हैं जैसा की वे भारत में करते थे। अपनी संस्कृति से इस प्रकार का जुड़ाव पश्चिमी मूल के नागरिकों को हमेशा से अपनी ओर खींचता रहा है। संस्कृति और परंपराओं को काफी हद तक भुला चुके भौतिकवादी पश्चिमी मूल के लोगों को यह बात काफी अच्छी लगती है। वे चाहते हैं कि वे इससे जुड़ें ताकि रंग विहीन हो चुकी उनकी जिंदगियां फिर से रंगीन हो सकें। इसके लिए वे भारतीय अध्यात्म और योग एवं आयुर्वेद का सहारा ले रहे हैं। वे इसे अच्छी तरह समझना चाहते हैं और किसी संस्कृति को समझने के लिए उसका भाषायी ज्ञान आवश्यक होता है। यही कारण है कि पश्चिमी देशों में भारतीय भाषा सीखाने के लिए ज्यादा से ज्यादा संस्थान खुल रहे हैं। ओहियो यूनिवर्सिटी, येल यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी जैसे अमेरिकी संस्थानों में हिंदी समेत 17 भारतीय भाषाओं को सीखाने के लिए अलग से डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं। साउथ कैरोलाईना यूनिवर्सिटी द्वारा दक्षिण एशियाई भाषाओं पर किए अपने शोध में पॉपुलरिटी के मामले में हिंदी को दूसरे स्थान पर रखा है।

राजकुमार शर्मा ,छात्र– लाईब्रेरी साइंस, दिल्ली

भला हो इस इंटरनेट और टी.वी. के फैलाव का जिसके कारण आज अधिक से अधिक पश्चिमी पर्यटक भारत की यात्रा करना चाहते हैं। वे भारत की भव्य विरासत और समृद्ध संस्कृति को देखना और जानना चाहते हैं। वे ताजमहल देखना चाहते हैं, वह बनारस के घाटों पर लोटना चाहते हैं, वे मैडोना और शकिरा की तरह मुंबई घूमना चाहते हैं और इनके लिए सबसे पहले वे हिंदी का औपचारिक ज्ञान चाहते हैं। इनके अलावा विदेशियों में भारत आने की संख्या में तीव्र बढोतरी देखने को मिली है। इसके पीछे है मेडिकल टूरिज्म में विस्तार। भारत ने अंतरिक्ष अनुसंधान, आईटी के साथ इस क्षेत्र में भी व्यापक प्रगति की है। भारत विश्व स्तरीय स्वास्थ सुविधाएं काफी कम कीमत पर उपलब्ध कराता है। जिसके कारण ज्यादा से ज्यादा विदेशी भारत आकर भारतीय पर्यटन का लुत्फ उठाने के साथ साथ स्वास्थ्य लाभ करना चाहते हैं। चूंकि कई ईलाज काफी लंबी अवधि के होते है तो लोग चाहते हैं कि उन्हें स्थानीय भाषा हिंदी का ज्ञान हो जाए तो उनके लिए बेहतर होगा। चौथी बात अमेरिकन कंपनियों की ज्यादा से ज्यादा नौकरियां आउटसोर्सिंग के जरिए भारत में आ गई हैं, वे लोग भी इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि उधर से फोन पर बात करने वाला कोई और नहीं , भारतीय ही है अतः हिंदी का औपचारिक ज्ञान हो जाए तो दोनों तरफ के लोगों को व्यवसायिक गतिविधियां चलाना आसान होगा। अतः विदेशों में लोग अब हिंदी को तरजीह देने लगे हैं।

विपुल शर्मा ,छात्र पत्रकारिता, दिल्ली विश्वविद्यालय

अमेरिकी सरकार द्वारा अमेरिकी स्कूलों में हिंदी को पढ़ाए दिए जाने की अनुमति देना विदेशों मे बढ़ती हिंदी की

महत्ता और लोकप्रियता को दर्शाता है। सन 2002 में करीब 3000 विदेशियों ने अमेरिकी विश्वविद्यालयों में हिंदी सीखने के लिए आवेदन किया। यह बात हिंदी छोड़ हिंगलिश में गिट–पिट करने वाले भारतीयों के लिए हैरानी और परेशानी की बात हो सकती है। पर विदेशों में रहने वाले हमारे प्रवासी भारतीयों के लिए गर्व की बात है। वे चाहते हैं उनके बच्चों को अंग्रेजी या वहां की प्रचलित भाषा के साथ हिंदी का ज्ञान अवश्य ले। हिंदी भाषा ज्ञान और फैलाव उन्हें अपने जड़ों से जुड़े रहने का अहसास दिलाता है। जिसके कारण हिंदी का प्रसार भारत की अपेक्षा विदेशों में जोर–शोर से हो रहा है। इसके लिए भारतीय ही नहीं वो विदेशी जिन्हें भारत के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी हो इसके प्रसार को गति देने में जुटा हुआ है।

राघेश्याम दिक्षीत,पत्रकार, आई.टी.वी., दिल्ली

लक्ष्मी मित्तल का स्टील किंग बनना, मुकेश अंबानी का विश्व में सबसे धनी व्यक्ति बनना, भारतीयों का वैश्विक आर्थिक मंच पर दबदबा कायम करना और भारत का विश्व की सबसे तेज गति से उभरने वाली आर्थिक महाशक्ति बनना आदि ऐसी घटनाएं जिसने पश्चिम में भारत के प्रति बने सपेरों के देश वाले मिथक को तोड़ दिया। लोग अब भारतीयों की क्षमताओं से प्रभावित हो कर नतमस्तक हो रहें हैं। भारत और भारतीय संस्कृति के प्रति विदशों में लोगों का झुकाव बढ़ता ही जा रहा है। अत: लोग भारत को जानने के लिए बॉलीवुड और हिंदी भाषा का सहारा ले रहे हैं। जिसका प्रतिफल है विदेशी त्योहारों और पार्टियों में बॉलीवुड की थीम सॉंग्स का बजना।

अब तक आपने सुना था की लोग शिक्षा लेने विदेशों को जाते रहे हैं। लेकिन स्थितियां उलट हो रही है। भारतीय शिक्षा के स्तर में सुधार से प्रभावित विदेशी अब अध्ययन के लिए भारत की ओर रुख करने लगे हैं। अत: वे चाहते हैं कि भारतीय भाषा का ज्ञान उन्हें हो तो उनके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। इसलिए अब भारतीय भाषा के प्रचार में और तेजी आ गई है। ■

ABVP demands private-public participation in higher education

Orissa unit of ABVP has sought radical changes in the state's academic policy, particularly in the field of higher education. Resolutions passed at the three-day conference held at Kendrapara, demanded more private-public participation in higher education followed by some other proposals like introduction of innovative education policy, increase in budget amount for education, introduction of industry oriented technical education, reduction in examination fees for intermediate classes, periodical evaluation of performance of teachers and immediate posting of permanent Principals in the Government-run colleges in the state.

The conference was inaugurated by international chief of Kriya Yoga, Paramahamsa Swami Prajnananda Giri and was presided over by ABVP's national president Dr Ram Naresh Singh. Shri Bishnu Das, Zonal Organising Secretary, in his presentation on the topic of self-reliant Orissa said that as an agrarian state, good irrigation facilities, technical knowledge for advanced farming, easily available bank loan and proper arrangement of marketing of farm products should be maid available to the farmers. On second day of the conference, the township witnessed a massive rally by the ABVP. A public meeting was held in the heart of the town which was attended by more than one thousand people.State Higher Education Minister Shri Sameer Dey inaugurated the exhibition and ABVP's state organising secretary Shri Gopinath Sahoo delivered the concluding speech. Shri B. Surendran, national co-organising secretary, Prant Pracharak of RSS were also present on the occasion.

परिषद् गतिविधियां

1857 क्रान्ति सन्देश यात्राओं का हरियाणा भर में भव्य स्वागत

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के उत्तर पश्चिम क्षेत्र के क्षेत्रिय संगठन मंत्री सुनील बंसल ने कहा कि 1857 स्वतंत्रता समर भारतीय जनमानस द्वारा स्वधर्म व स्वराज्य की प्राप्ति के लिए किया गया प्रथम राष्ट्रीय प्रयास था । वह अभाविप हरियाणा प्रदेश द्वारा 15 नवम्बर से 23 नवम्बर तक निकाली गई क्रांति संदेश यात्राओं के समापन कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे । उन्होंने कहा कि 1857 के महासंग्राम को मात्र विद्रोह या गदर कहना अंग्रेजी मानसिकता का परिचायक है । वास्तव में यह आन्दोलन स्वधर्म को बचाने और स्वराज्य को प्राप्त करने तथा स्वाभिमान स्वावलंबन की लडाई थी । आन्दोलन के प्रतीक चिन्ह बने 'रोटी और कमल के फूल' । इस आन्दोलन मे तीन लाख लोगों ने भारत माता की आज़ादी के लिए प्राणां की आहूति दी । उन्होंने क्रांति को असफल कहने वालों को आड़े हाथों लिया। कार्यक्रम में सेवानिवृत्त जनरल श्री.अविनाश चन्द्र मंगला, पूर्व मंत्री श्री बृजमोहन सिंगला, प्रसिद्ध चिकित्सक डॉ. कंवर सेन गोयल, डा.मदन गोयल, श्री. सुरेन्द्र सिंह व तीनों यात्रा संयोजकों ने भी अपने विचार रखे ।

1857 क्रांति संदेश यात्रा का शुभारम्भ करते हुए अस्थल बोहर गद्दी प्रमुख व विधायक महंत चांदनाथ योगी ने कहा कि 1857 की क्रांति एक संगठित, योजनाबद्ध राष्ट्रीय प्रयास था। यह भारतीय इतिहास का वह स्वर्णिम पृष्ठ था जब देश का हर व्यक्ति अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए खड़ा हो गया । उन्होंने कहा कि 1857 की क्रांति के कारण ही हम 90 वर्षों में अपनी मातृभूमि को आजाद करा पाए । उन्होंने युवाओ का आहवान किया जिस प्रकार भारत के अनेक शहीदों ने 1957 की क्राति से प्रेरणा लेकर अपना बलिदान दिया । आज भी उसे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है । हमें वर्तमान चुनौतियों का सामना करने के लिए संस्कारित और संगठित होकर एकजुट होना पडेगा ।

Western U P

48 वां प्रान्तीय अधिवेशन

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् का 48वां प्रान्तीय अधिवेशन 21–23 दिसम्बर 2007 को फिरोजाबाद के एस.आर. के. (डिग्री) महाविद्यालय में हुआ । अधिवेशन मे शहीद भगत सिंह के नाम से नगर बसाया गया, जिसमें मुख्य सभागार महारानी लक्ष्मीबाई के नाम से और प्रदर्शनी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख स्व.अधीश जी के नाम से लगाई गई । जिसमें स्व0 अधीश जी की जीवनी भी लगाई गई और प्रदर्शनी में विद्यार्थी परिषद् के रचनात्मक आन्दोलनात्मक एवं विशेष कार्यक्रमों को लगाया गया। परिसर में शहीद भगत सिंह के जीवन परिचय भी लगाया गया ।

अधिवेशन का उद्घाटन मुख्य अतिथि माननीय हृदयनारायण दीक्षित,प्रमुख स्तम्भकार एवं पूर्व मन्त्री उ.प्र. शासन ने दीप जलाकर किया । मुख्य वक्ता श्री.नागेश ठाकुर जी ने विद्यार्थी परिषद के कार्य एवं इतिहास के बारे मे बहुत सी जानकारी दी ।

शोभायात्रा शहर के मुख्य मार्ग से होकर विवेकानन्द चौंक पर समाप्त हुई। खुला अधिवेशन में छात्र नेता श्री. हरिवेन्द्र सिंह यादव ने शिक्षा के भारतीयकरण पर जानकारी दी । कु.कल्पना ने भारतीय जगत में स्त्री का योग की जानकारी दी । अध्यक्षता श्री मनीष असीजा,चेयरमैन नगर फिरोजाबाद ने की, श्री वी. सुरेन्द्रन्,राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री छात्र छात्राओं को सम्बोधन में कहा कि रामसेतु की रक्षा के लिये देश का प्रत्येक नागरिक दृढ है ।

मन्त्री प्रतिवेदन में प्रदेश मन्त्री ने साल में संगठन के हुए कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी । चुनाव अधिकारी श्री.राजनारायण ने नये अध्यक्ष, श्री राकेश चतुर्वेदी (मथुरा), प्रदेश मन्त्री श्री अरविन्द सिंह (बरेली) की घोषणा की।

Madhya Bharat

भोपाल में एक लाख कार्यकर्ता करेंगे आन्दोलन

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् की प्रांत कार्यकारी परिषद की दो दिवसीय बैठक 3 फरवरी को सम्पन्न हुई । बैठक में शिक्षा जगत के वर्तमान परिदृश्य में सुधार हेतु एक मॉग प्रस्ताव पारित किया गया । प्रस्ताव में परिषद ने प्रदेश सरकार से यह मॉग भी की गई कि संगठित अपराध एवं आतंकवादी गतिविधि नियंत्रण विधेयक 2007 को लागू करें ताकि प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हो सके ।

प्रतिनिधियों ने अपने–अपने विचार परिषद् के पदाधिकारियों के समक्ष रखे । विभिन्न सत्रों मे आयोजित इस बैठक के समापन के पूर्व अभाविप द्वारा सर्वसम्मति से मॉग प्रस्ताव पारित किया गया । मॉग की गई कि सरकार प्राइवेट, व्यावसायिक, शैक्षणिक संस्थाओ में प्रवेश परीक्षा की एजेंसी तय कर अपीलीय अधिकारी की नियुक्ति शीघ्र करे एवं नीति तय करते हुए हाईकोर्ट के निर्देशो का पालन सुनिश्चित करे।

प्रांत मंत्री श्री हितेश शुक्ला ने बताया प्रदेश के

परिषद् गतिविधियां

1857 क्रान्ति सन्देश यात्राओं का हरियाणा भर में भव्य स्वागत

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के उत्तर पश्चिम क्षेत्र के क्षेत्रिय संगठन मंत्री सुनील बंसल ने कहा कि 1857 स्वतंत्रता समर भारतीय जनमानस द्वारा स्वधर्म व स्वराज्य की प्राप्ति के लिए किया गया प्रथम राष्ट्रीय प्रयास था । वह अभाविप हरियाणा प्रदेश द्वारा 15 नवम्बर से 23 नवम्बर तक निकाली गई क्रांति संदेश यात्राओं के समापन कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे । उन्होंने कहा कि 1857 के महासंग्राम को मात्र विद्रोह या गदर कहना अंग्रेजी मानसिकता का परिचायक है । वास्तव में यह आन्दोलन स्वधर्म को बचाने और स्वराज्य को प्राप्त करने तथा स्वाभिमान स्वावलंबन की लड़ाई थी । आन्दोलन के प्रतीक चिन्ह बने 'रोटी और कमल के फूल' । इस आन्दोलन मे तीन लाख लोगों ने भारत माता की आजादी के लिए प्राणां की आहूति दी । उन्होंने क्रांति को असफल कहने वालों को आड़े हाथों लिया। कार्यक्रम में सेवानिवृत्त जनरल श्री.अविनाश चन्द्र मंगला, पूर्व मंत्री श्री बृजमोहन सिंगला, प्रसिद्ध चिकित्सक डॉ. कंवर सेन गोयल, डा.मदन गोयल, श्री. सुरेन्द्र सिंह व तीनों यात्रा संयोजकों ने भी अपने विचार रखे ।

1857 क्रांति संदेश यात्रा का शुभारम्भ करते हुए अस्थल बोहर गद्दी प्रमुख व विधायक महंत चांदनाथ योगी ने कहा कि 1857 की क्रांति एक संगठित, योजनाबद्ध राष्ट्रीय प्रयास था। यह भारतीय इतिहास का वह स्वर्णिम पृष्ठ था जब देश का हर व्यक्ति अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए खड़ा हो गया । उन्होंने कहा कि 1857 की क्रांति के कारण ही हम 90 वर्षों में अपनी मातृभूमि को आजाद करा पाए । उन्होंने युवाओ का आहवान किया जिस प्रकार भारत के अनेक शहीदों ने 1957 की क्रांति से प्रेरणा लेकर अपना बलिदान दिया । आज भी उसे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है । हमें वर्तमान चुनौतियों का सामना करने के लिए संस्कारित और संगठित होकर एकजुट होना पडेगा ।

Western U P

48 वां प्रान्तीय अधिवेशन

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् का 48वां प्रान्तीय अधिवेशन 21–23 दिसम्बर 2007 को फिरोजाबाद के एस.आर. के. (डिग्री) महाविद्यालय में हुआ । अधिवेशन में शहीद भगत सिंह के नाम से नगर बसाया गया, जिसमे मुख्य सभागार महारानी लक्ष्मीबाई के नाम से और प्रदर्शनी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख स्व.अधीश जी के नाम से लगाई गई । जिसमें स्व0 अधीश जी की जीवनी भी लगाई गई और प्रदर्शनी में विद्यार्थी परिषद् के रचनात्मक आन्दोलनात्मक एवं विशेष कार्यक्रमों को लगाया गया। परिसर में शहीद भगत सिंह के जीवन परिचय भी लगाया गया ।

अधिवेशन का उद्घाटन मुख्य अतिथि माननीय हृदयनारायण दीक्षित,प्रमुख स्तम्भकार एवं पूर्व मन्त्री उ.प्र. शासन ने दीप जलाकर किया । मुख्य वक्ता श्री.नागेश ठाकुर जी ने विद्यार्थी परिषद के कार्य एवं इतिहास के बारे मे बहुत सी जानकारी दी ।

शोभायात्रा शहर के मुख्य मार्ग से होकर विवेकानन्द चौंक पर समाप्त हुई। खुला अधिवेशन में छात्र नेता श्री. हरिवेन्द्र सिंह यादव ने शिक्षा के भारतीयकरण पर जानकारी दी । कु.कल्पना ने भारतीय जगत में स्त्री का योग की जानकारी दी । अध्यक्षता श्री मनीष असीजा,चेयरमैन नगर फिरोजाबाद ने की, श्री वी. सुरेन्द्रन्,राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री छात्र छात्राओं को सम्बोधन में कहा कि रामसेतु की रक्षा के लिये देश का प्रत्येक नागरिक दृढ़ है ।

मन्त्री प्रतिवेदन में प्रदेश मन्त्री ने साल में संगठन के हुए कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी । चुनाव अधिकारी श्री.राजनारायण ने नये अध्यक्ष, श्री राकेश चतुर्वेदी (मथुरा), प्रदेश मन्त्री श्री अरविन्द सिंह (बरेली) की घोषणा की।

Madhya Bharat

भोपाल में एक लाख कार्यकर्ता करेंगे आन्दोलन

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् की प्रांत कार्यकारी परिषद की दो दिवसीय बैठक 3 फरवरी को सम्पन्न हुई । बैठक में शिक्षा जगत के वर्तमान परिदृश्य में सुधार हेतु एक माँग प्रस्ताव पारित किया गया । प्रस्ताव में परिषद ने प्रदेश सरकार से यह माँग भी की गई कि संगठित अपराध एवं आतंकवादी गतिविधि नियंत्रण विधेयक 2007 को लागू करें ताकि प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हो सके ।

प्रतिनिधियों ने अपने–अपने विचार परिषद् के पदाधिकारियों के समक्ष रखे । विभिन्न सत्रों में आयोजित इस बैठक के समापन के पूर्व अभाविप द्वारा सर्वसम्मति से माँग प्रस्ताव पारित किया गया । माँग की गई कि सरकार प्राइवेट, व्यावसायिक, शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश परीक्षा की एजेंसी तय कर अपीलीय अधिकारी की नियुक्ति शीघ्र करे एवं नीति तय करते हुए हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करे।

प्रांत मंत्री श्री हितेश शुक्ला ने बताया प्रदेश के

राजनीतिज्ञों द्वारा विश्वविद्यालयों में भ्रष्ट कुलपतियों की नियुक्तियां की जा रही हैं । राष्ट्रभक्ति आंदोलनों के माध्यम से समाज और देश में फैली विकृतियों को दूर करना परिषद के कार्यकर्ताओं का ध्येय है । स्कूल, कालेज व विश्वविद्यालयों में विभिन्न शैक्षणिक समस्याओं को लेकर परिषद के लगभग एक लाख कार्यकर्ताओं द्वारा नवीन सत्र में भोपाल में प्रभावी आन्दोलन व प्रदर्शन किया जायेगा ।

प्रांत छात्रा प्रमुख सुश्री चतुर्वेदी ने बताया खरगोन जिले में इस बार परिषद में 951 छात्राओं ने सदस्यता ग्रहण की । छात्राओं में विभिन्न आंदोलन व गतिविधियों के प्रति जागरूकता लाने के लिए छुट्टियों में विशेष व्यक्तित्व विकास शिविर आयोजित किया जाएगा । इसमें छात्रा शक्ति को जागरूक बनाया जाऐगा ।

Eastern U P

47th State Conference of ABVP

Shri Prakash Singh, former Director General of Uttar Pradesh Police, has stressed the need to enact stern law than POTA to prevent growing terrorism in the country. He said the situation of national security is deteriorating day-by-day in the country and terrorism has spread all over the country assuming a dangerous form in Uttar Pradesh. Shri Singh was addressing the 47th state convention of ABVP in Varanasi on February 3. More than 1000 delegates from 54 places of the state participated in the conference, which began on February 2 with the inauguration of an exhibition on 1857 War of Independence by Swami Avimukteshwarananda from Kashi Vidyamath.

Shri Atul Kothari, joint organising secretary of ABVP, said the commercialisation of education would enhance division in the society. He said the self-financed education system is nothing but commercialisation in which only the rich could get higher education. He stressed the need to improve the quality of education. He said the ABVP has taken some steps in this regard by organising educational and intellectual seminars all over the country to educate the countrymen and policy makers. The ABVP would continue to educate the society for this objective.

Earlier, Dr Payal Sirohi, national vice president of ABVP said it is the era of change and the Indian youth have great potential of bringing the desirable change in the country. Dr Vivek Nigam, newly elected state president, appealed to the youth to present an ideal of their personality. Shri Suryanath, state organising secretary of ABVP, said workers of ABVP are working for strengthening the national unity and integrity. On first day of the convention, Dr Vivek Nigam and Shri Santosh Kumar were elected state president and state secretary respectively

Jharkhand

छात्र हितों की अनदेखी के खिलाफ आंदोलन

सीनेट की बैठक में छात्र हितों की अनदेखी किए जाने के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने 2 फरवरी को रांची विश्वविद्यालय मुख्यालय में अनिश्चितकालीन तालाबंदी कर कामकाज ठप कर दिया।

तालाबंदी के दूसरे दिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता दस बजे विश्वविद्यालय मुख्यालय पहुंचे व मुख्यद्वार के पास धरने पर बैठ गए। छात्र कुलपति को बुलाने की मांग कर रहे थे। साढे ग्यारह बजे विश्वविद्यालय के कुलानुशासक, डीएसडब्लू, परीक्षा नियंत्रक व उप कुलसचिव छात्रों के साथ बात करने के लिए धरनास्थल पहुंचे। उन्होंने छात्रों को धरना समाप्त करने व वार्ता करने के लिए विश्वविद्यालय का गेट खोलने को कहा। छात्रों ने अधिकारियों की बात नहीं मानी और कुलपति को बुलाए जाने की मांग पर अडे रहे। बात नहीं बनते देख विश्वविद्यालय अधिकारी चले गए। लगभग आधा घंटे बाद विश्वविद्यालय अधिकारियों का एक और दल बातचीत के लिए पहुंचा। अधिकारियों ने विश्वविद्यालय अधिनियम का हवाला देते हुए कहा कि सीनेट की बैठक फिर से नहीं बुलाई जा सकती है। इस पर छात्रों ने कहा कि विश्वविद्यालय अधिनियम में सीनेट की बैठक बुलाने का प्रावधान है, और जब तक कुलपति नहीं आते वे धरना समाप्त नहीं करेंगे। इधर कुलपति ने साफ तौर पर कहा कि पहले ताला खोला जाय, इसके बाद वे आएंगे। आंदोलन के दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्रशासन विरोधी नारे लगाए।

Himachal Pradesh

नंदीग्राम हिंसा विरोध अभियान

नंदीग्राम हिंसा के विरोध मे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, कुल्लू के कार्यकर्ताओं ने 6 फरवरी को राष्ट्रीय अभियान कालेज परिसर से शुरू किया। इस दौरान विद्यार्थियों ने शहर मे रैली निकाली। रैली को संबोधित करते हुए विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक श्री गौरव भारद्वाज ने कम्युनिस्टों पर कड़े प्रहार करते हुए कहा कि 30 वर्षों से माकपा (सीपीआई व एम) के नेतृत्व मे सत्तासीन वाममोर्चा सरकार ने भय एव आंतक के बल पर तानाशाही विचारधारा को बल दिया है। उन्होंने कहा कि कम्युनिस्टों ने कभी भी प्रजातंत्र के आधारभूत स्तंभों को स्वायतता से पनपने नहीं दिया।

उन्होंने नंदीग्राम का हवाला देते हुए कहा कि 14 मार्च 2007 को नंदीग्राम मे अपनी भूमि से बेदखली का विरोध कर रहे सैकड़ों निर्दोष किसानों पर वाम मोर्चा सरकार के इशारे पर पुलिस ने जमकर गोलियां चलाई, जिसमें 15 लोग मारे गए और दो सौ से अधिक घायल हुए। तबसे लेकर अब तक हिंसा व आंतक का वातावरण एवं निरंतर गोलीबारी जारी है जिससे हजारों लोगों को औद्योगिकरण के नाम पर खेत एव खलिहान से उजाड़ा जा रहा है। भारद्वाज ने कहा कि कम्युनिस्टों का असली चेहरा नंदीग्राम एंव सिंगूर में बेनकाब हो गया है। वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य मार्क्सवादी डायर बनकर उभरे हैं।

उन्होंने कहा कि परिषद इसका विरोध करता है और तब तक करता रहेगा जब तक पश्चिम बंगाल की खूनी साम्यपंथी सरकार को बर्खास्त कर आरोपियों को सजा नहीं मिल जाती। परिषद के विद्यार्थियों ने एकजुट होकर विद्यार्थी महामहिम राष्ट्रपति से मांग की कि पश्चिम बंगाल सरकार को बर्खास्त किया जाए ताकि किसानों को न्याय मिल सके।

Himachal governor for positive attitude among youths

Himachal Governor Shri V.S. Kokje, stressed upon the importance of optimism in life and appealed the youth to adopt a positive attitude to progress ahead. He was speaking in State Level General Knowledge Competition Prize Distribution Function organized by Akhil Bhartiya Vidyarthi Parishad at Solan today.

Governor said India's rich human resources and education should be meaningful and based on values.

Kokje paid tributes to Netaji Subhash Chander Bose and added that lives of great personalities like Netaji and Veer Sawarkar were an inspiration to youth.Chetan Sharma of GSSS Mahunag, Sunil of JPSS Palampur and Sandeep Sharma of MSS Bhota, Hairmpur won 1st, 2nd and 3rd prizes respectively.

Himachal Pradesh

26th State Conference

Andhra Pradesh High Court retired judge and Kshetra Sanghachalak Shri S. Parvata Rao while speaking as the chief guest at the valedictory function of the 26th state conference exhorted the ABVP delegates to become powerful to achieve the objective of united Hindu rashtra amidst mounting problems and ills plaguing the country. In this programme World Organistation of Students and Youth secretary general Shri Ramesh Pappa while speaking as main speaker reminded about uncompromising and continuous fight to safeguard student interests and to focus on the problems being faced by them. He reminded that ABVP was founded in 1949 with lofty ideals and became the biggest students union in the country.

Shri Badrinath, editor of Economics Times while speaking as the chief guest in Gouri ShankarYuva Puraskar 2008 programme highlighted that India is marching ahead very fast and youth working with vigor, India becoming superpower is not far away.

Shri M. Sunil Reddy recipient of Gouri Shankar Yuva Puraskar 2008 while speaking on the occasion exhorted the students to cultivate the thoughts of providing basic facilities to the rural poor and working for social justice. Shri K.N. Raghunandan South India Kshetra

organising secretary participating as a guest asked the students to emulate the late Shri Gouri Shankarji and dedicate for the good of the country.

The 26th state conference of ABVP was held at Hanumakonda, Warangal District, A.P. on January 4, 2008. Former BJP MP Shri C. Janga Reddy gave a call to youth of India to contribute for building modern India utilising nationalistic thoughts strengthened with ideological spirit and self-confidence. In this programme ABVP state president Dr. T. Penchalaiah lauded the services of the late Sama Jaganmohan Reddy who worked tirelessly for ABVP and gave his life for national flag with his ideological conviction. South Eastern Kshetra organising secretary Shri Srinivas said that it was due to ABVP's efforts and sacrifice of lives of 47 members Naxalism has been erased out from the university campuses.

'क्रांति संदेश यात्रा'

1857 की क्रांति अंग्रेजों के विरुद्ध सशक्त संगठित सैनिक संघर्ष था, लेकिन पाठ्यक्रम में इसे 'सैनिक विद्रोह' बताया जाता है। यह शहीदों का अपमान है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् इस तरह के पाठ्यक्रम को गढ़ने वालों की निन्दा करती है तथा प्रथम स्वतंत्रता आन्दोलन के सही स्वरूप को जन–जन तक पहुंचाने के लिए वचनबद्ध है। अपने इसी संकल्प को पूरा करने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् ने '1857 स्वतंत्रता समर क्रांति सन्देश यात्राओं' का आयोजन किया है।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऐसी ही एक यात्रा गत 17 जनवरी को शहीद रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, ठाकुर रोशन सिंह और राजेन्द्र लाहड़ी की जन्मभूमि शाहजहांपुर से चली। दूसरी यात्रा कभी देश की राजधानी रहे आगरा से 19 जनवरी को प्रारम्भ हुई। दोनों यात्राएं उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति से जुड़े महत्वपूर्ण स्थानों से होती हुई 23 जनवरी को 1857 की क्रांति के उदगम् स्थल मेरठ पहुंचीं। क्रांति सन्देश यात्रा के दौरान विभिन्न स्थानों पर शहीदों के सम्मान में भव्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। मार्ग में शहीदों के चित्रों से सुसज्जित दोनों रथों पर पुष्प वर्षा की गई।

शाहजहांपुर से शुरू हुई यात्रा को शारदापीठ के शंकराचार्य स्वामी राज राजेश्वराश्रम जी महाराज ने रवाना किया। इस अवसर पर आयोजित सभा में उन्होंने कहा कि देश के युवक महावीर हनुमान जी से प्रेरणा लेकर देश की संस्कृति को आहत करने वाली समस्याओं से निपटने के लिए प्रयास कर रहे है, विद्यार्थी परिषद् को उनका नेतृत्व करना चाहिए।

शाहजहांपुर के बाद तिलहर में राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.) के छात्रों ने रथ में रखे 'शहीद कलश' को पुष्पाञ्जलि अर्पित की। फरीदपुर में डेढ़ सौ नेशनल कैडिट कोर्पस (एन.सी.सी.) के जवानों ने परेड कर शहीदों को सलामी दी।

आगरा से क्रांति यात्रा को रवाना करते हुए अ.भा. विद्यार्थी परिषद् के राष्ट्रीय महामंत्री श्री सुरेश भट्ट ने कहा कि छात्रों के संघर्ष द्वारा ही परिवर्तन सम्भव होता है। इसलिए विद्यार्थी परिषद् ने शहीदों के सन्देश को जन–जन तक पहुंचाने के लिए इस सन्देश यात्रा का आयोजन किया है।

आगरा से शुरू हुई यात्रा का मथुरा में होली गेट पर सभा आयोजित कर भव्य स्वागत किया गया। सासनी में नगर भ्रमण किया गया। अलीगढ़ में कई स्थानों पर सभाएं आयोजित की गईं। बुलन्दशहर के काला आम चौराहे पर भव्य स्वागत किया गया। काला आम चौराहा क्रांति से जुड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। मोदीनगर, गाजियाबाद, मुरादनगर में भी क्रांति यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। मोदी नगर में शहीद चौक पर एक बड़ी सभा का आयोजन किया गया।

23 जनवरी को दोनों यात्राएं विभिन्न मार्गों से होते हुए मेरठ पहुंची, जहां नगर में कई स्थानों पर सभाएं आयोजित की गईं। व्यापारियों, वकीलों, सामाजिक संगठनों तथा पुलिसकर्मियों ने यात्राओं का भव्य स्वागत किया। शहर में स्थित औघडनाथ मन्दिर परिसर में समापन समारोह किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र तथा प्रबुद्धजन उपस्थित थे। समापन समारोह को सम्बोधित करते हुए पूर्व केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री स्वामी चिन्मयानन्द जी ने कहा कि आज आतंकवाद रूपी रावण को मारने के लिए राम की जरूरत है।

दोनों क्रांति संदेश यात्राओं में कुल मिलाकर 123 स्थानों पर 428 कार्यक्रम आयोजित हुए जिसमें लगभग 55 महाविद्यालयों में सभाएं हुईं, लगभग 2 लाख छात्र–छात्राओं एवं नागरिकों ने सहभाग किया। पूरे प्रदेश में यात्रा के माध्यम से देशभक्ति का वातावरण बना रहा और स्थान–स्थान पर 1857 के क्रांतिकारियों का स्मरण किया गया तथा सभी स्थानों पर विद्यार्थी परिषद् के स्थानीय कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे।

Glimpses of Silver Jubilee State Conference of West Bengal

D Ed Students in Mumbai protesting and polishing shoes against the Govt's decision free internship of six months.

क्रांति संदेश यात्रा–राजस्थान

अभाविप हरियाणा प्रदेश द्वारा 15 से 23 नवम्बर तक निकाली गई क्रांति संदेश यात्रा

"IMPACT OF GLOBALISATION ON EDUCATION"
International Seminar

Delegates from Nepal

Mr.Jasem
Iran

Ms.Arene
Australia

Ms.Sandrine
Mauritius

Ms.Florene
France

Ms.Yvonne
Kenya

W
O
S
Y